शक्ति, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो विवेक के साथ ही लाभप्रद हो सकती है। -महास्थविर शान्ति मुनि

जयपुर ■ दिल्ली से प्रकाशित

बिज़नेस रेमेडीज

वर्ष : 13 | अंक : 181 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए स्वीकृत **व्यापार एवं विकास की आवाज** मूल्य : 3 रुपए | पेज : 8 दैनिक | www.businessremedies.com

जयपुर | सोमवार 13 जुलाई, 2026

समाचार पत्र की प्रति प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करें: 9462549061

भारत में अगले साल 15 अगस्त से शुरू होगी बुलेट ट्रेन : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा 15 अगस्त, 2027 से चरणबद्ध तरीके में शुरू होगी और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएएचएसआर) कॉरिडोर का सूरत-बिलिमोरा सेक्शन देश का पहला हाई-स्पीड रेल रूट बनेगा। 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जिससे पूरे रूट के पूरा होने से पहले ही प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से चालू हो सकेंगे। सूरत-बिलिमोरा सेक्शन के शुरू होने के बाद, बाकी सेक्शन - जैसे वापी-सूरत, वापी-अहमदाबाद, अहमदाबाद-ठाणे और अहमदाबाद-मुंबई को धीरे-धीरे खोला जाएगा। हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्रालय ने वैष्णव ने कहा कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अपने अगले चरण में पहुंच गया है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का काम चल रहा है और इसे चरणों में शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत सूरत-बिलिमोरा सेक्शन से होगी।

रूस से कच्चे तेल का आयात 34% बढ़ा

चीन के बाद रूसी हाइड्रोकार्बन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना भारत

जामनगर, पारादीप, कोच्चि और वाडिनार रिफाइनरियों ने बढ़ाई खरीद

वैश्विक कीमतों में गिरावट के बीच रूस के निर्यात राजस्व पर दबाव

नई दिल्ली | बीआर न्यूज नेटवर्क
businessremedies.com

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच भारत ने जून में रूस से कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की रिपोर्ट के अनुसार, जून में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात 34 प्रतिशत बढ़कर 4.5 अरब यूरो पहुंच गया। इसके साथ ही भारत चीन के बाद रूस से हाइड्रोकार्बन खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया।

आयात में 34 प्रतिशत की हुई जोरदार बढ़ोतरी

सीआरईए की रिपोर्ट के मुताबिक जून में भारत ने रूस से 4.5 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा, जो मई की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है। जून में भारत के कुल रूसी जीवाश्म ईंधन आयात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी 83 प्रतिशत रही। कुल रूसी हाइड्रोकार्बन आयात का मूल्य 5.5 अरब यूरो रहा, जिससे भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया।

रिफाइनरियों ने बढ़ाई रूसी तेल की खरीद

रिपोर्ट के अनुसार, देश की प्रमुख रिफाइनरियों ने जून में रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी में आयात 150 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पारादीप रिफाइनरी में 126 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। भारत पेट्रोलियम की कोच्चि रिफाइनरी में खरीद 83 प्रतिशत और नायरा एनर्जी की वाडिनार रिफाइनरी में 45 प्रतिशत बढ़ी।

रूस के निर्यात को मिला सहारा, राजस्व पर दबाव

भारत की बढ़ती मांग के चलते जून में रूस के कच्चे तेल के निर्यात की मात्रा में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम रहने के कारण रूस की निर्यात आय घटकर 348 मिलियन यूरो प्रतिदिन रह गई। कुल जीवाश्म ईंधन निर्यात से होने वाली आय भी एक प्रतिशत घटकर 734 मिलियन यूरो प्रतिदिन दर्ज की गई।

तेल उत्पाद और कोयले का आयात भी बढ़ा

रिपोर्ट में बताया गया कि कच्चे तेल के अलावा भारत ने रूस से 488 मिलियन यूरो के तेल उत्पाद और 444 मिलियन यूरो का कोयला भी आयात किया। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध रूसी ऊर्जा संसाधनों के कारण भारत की खरीद आगे भी मजबूत बनी रह सकती है।

'हाई-फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर' से छोटे कारोबारियों को मिलेगी नई ताकत, अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार : सीएआईटी

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ 'सीएआईटी' (कैट) ने केंद्र सरकार द्वारा 14 जुलाई को 'हाई-फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर' लॉन्च करने के फैसले का स्वागत किया है। कैट का कहना है कि यह पहल छोटे व्यापारियों, खुदरा कारोबारियों, एमएसएमई और उद्यमियों को मजबूत बनाएगी तथा भारत की आर्थिक विकास यात्रा को नई गति देगी। कैट ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आर्थिक शासन को अधिक आधुनिक, गतिशील और डेटा आधारित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया।

यह हाई-फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का लगभग वास्तविक समय में आकलन करेगा। इसके लिए जीएसटी संग्रह, यूपीआई लेनदेन, ई-वे बिल, माल ढुलाई, बिजली खपत, बैंकिंग गतिविधियां, डिजिटल कॉमर्स और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों को एक साथ जोड़ा जाएगा। इससे सरकार को तेजी और अधिक सटीकता के साथ नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही उभरती आर्थिक चुनौतियों की समय रहते पहचान कर आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। कैट के महासचिव और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया, जीएसटी, यूपीआई और तकनीक आधारित सुशासन जैसी पहलों के जरिए आर्थिक पारदर्शिता और दक्षता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 'हाई-फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर' इस परिवर्तनकारी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण अध्याय है, जो भारत को दुनिया की सबसे उन्नत और डेटा आधारित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस पहल का सबसे अधिक लाभ देश के छोटे व्यापारी, रिटेल कारोबारी, एमएसएमई और उद्यमियों को मिलेगा।

बिज़नेस रेमेडीज

वर्ष : 13 । अंक: 181

सम्पादकीय

भारतीय रेल का होता निरंतर विस्तार, पर अब भी है कई चुनौतियां

भारतीय रेल, यात्रियों की सुविधाओं के लिए निरंतर विस्तार तो कर रही है, पर अभी उसके समक्ष कई चुनौतियां भी है। इसका समाधान भी इसे जल्द करना होगा। मानसून के दौरान अधिकांश रेलों का रद्द होना और देरी से गतव्य स्थलों पर पहुंचना एक आम बात है। इन दिनों कई ट्रेनें तो पांच से छह घंटे देरी से गतव्य स्थानों पर पहुंच रही है। ऐसे में यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रेल मंत्रालय वैसे तो यात्रियों की सुविधाओं को देने के लिए सुरक्षा, गति और आधुनिक तकनीक पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। उसका लक्ष्य रेलवे को अधिक सुरक्षित, तेज, स्वच्छ और डिजिटल बनाना है। रेलों को गति देने के लिए कई योजनाएं भी संचालित की है। इनमें देशभर में वंदे भारत चेयर कार तथा वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा भविष्य में इन ट्रेनों की संख्या में और वृद्धि की योजना है। इसके अलावा स्टेशनों पर नई प्रतीक्षालय, एस्केलेटर, लिफ्ट, बेहतर शौचालय, फूड कोर्ट, डिजिटल सूचना बोर्ड, मुफ्त वाई-फाई और दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कवच नामक स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। यह प्रणाली सिग्नल तोड़ने, अधिक गति और ट्रेन टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है। हाल ही में कई नए रेल मार्गों पर इसके विस्तार को मंजूरी भी दी गई है। हजारों नए जनरल (नॉन-एसी) कोच जोड़े जाने की योजना है। अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का विस्तार किया जा रहा है ताकि कम किराए में बेहतर यात्रा उपलब्ध हो सके। बेहतर डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए टिकट बुकिंग प्रणाली को और तेज बनाया जा रहा है। ट्रेन की लाइव जानकारी, सीट उपलब्धता और यात्री सेवाओं को मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। स्टेशन और ट्रेनों में डिजिटल सूचना व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है। कई प्रमुख रेल मार्गों को 160 किमी/घंटा तक की गति के लिए उन्नत किया जा रहा है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी कार्य जारी है, जो भारत में हाई-स्पीड रेल का नया अध्याय होगी। अधिकांश रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और शेष कार्य जारी है। भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेन जैसी हरित तकनीकों पर भी काम हो रहा है।

BR सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी विशेष लेख व्यक्तिगत सोच के आधार पर है।

संपादक

सादगी ही जिन्दगी का वास्तविक सौन्दर्य है

ललित गर्ग

कहते हैं ना लाइफ जितनी सिंपल होगी उतनी ही अच्छी एवं आनन्दमय होगी। हर इंसान सुन्दर एवं आकर्षक दिखना चाहता है, दीखने में बनावटीपन है, प्रदर्शन है, अनुकरण है, जबकि वास्तविक सौन्दर्य सादगी में है। सबसे सुन्दर दिखने की चाह में एक इंसान दूसरे इंसान तक को नहीं छोड़ता। संतुलित, शांत, आनन्दयम एवं सार्थक जिन्दगी के लिये सादगी का बहुत महत्व है, इसलिये 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लेखक और दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो के सम्मान में मनाया जाता है। इसी दिन इनका जन्म हुआ था। थोरो को उनकी पुस्तक 'वाल्डेन' के लिए जाना जाता था, जो कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स में वाल्डेन तालाब के पास एक छोटे से केबिन में एक साधारण जीवन जीने के उनके अनुभवों का वर्णन करती है। उनका मानना था कि लाइफ को केवल पैसे और अनावश्यक चीजों को हासिल करने के लिए ही बस खत्म ना करें। बल्कि हमारा ध्यान नेचर, ज्ञान, सेल्फ डिपेंडेंट और खुद का रास्ता बनाने पर होना चाहिए, जिसके लिए सादगीपूर्ण जीवन जीना बहुत जरूरी है। जैसा कि थोरो ने खुद कहा था- ''जैसे-जैसे आप अपने जीवन को सरल बनाते जाएँगे, ब्रह्मांड के नियम सरल होते जाएँगे।'' हेनरी डेविड थोरो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर काम में माहिर थे, एक लेखक, एक पर्यावरणविद, एक उन्मूलनवादी, एक कवि, लेकिन आप शायद उन्हें अपने हाई स्कूल की अंग्रेजी कक्षा से एक पारलौकिकवादी के रूप में याद करते हों। वह और उनके समकालीन पारलौकिकवादी, सरल शब्दों में मानते थे कि लोगों के पास अपने बारे में ऐसा ज्ञान होता है जो उनके जीवन में सभी बाहरी ताकतों से परे होता है। वे उन भावनाओं से बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए एक सरल जीवन जीने की वकालत करते थे।

महान् लोगों का मानना है कि प्रतिभा भगवान ने दी है, विनम्र रहें। प्रसिद्धि इंसान ने दी है, कृतज्ञ रहें। अहंकार खुद की देन है, इसलिए सजग रहें। जीवन में सरलता और सादगी बहुत जरूरी है। हमारे सपनों और खुशियों की हर राह शरीर से होकर ही गुजरती है, पर हम इसकी अनदेखी करते रहते हैं। नतीजा, मन के साथ शरीर से भी अस्वस्थ्य बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, ''शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। तभी मन मजबूत होगा और विचारों में स्पष्टता भी आएगी।'' बढ़ते कचरे को देखते हुए पश्चिमी देशों में 'मिनिमलिज्म' की बातें हो रही हैं। कम के साथ रहने की इस मिनिमलिस्टिक जीवनशैली का असर कपड़े, पैसे, कला, संगीत, सोच से लेकर इंटीरियर और मेकअप हर जगह अपनाने की कोशिशें बढ़ी हैं। हालांकि भारतीय दर्शन बहुत पहले से ही सादगी से जीने की तरफदारी करता रहा है। जैन दर्शन में बाकायदा इसके लिए 'अपरिग्रह' शब्द दिया गया है। यानी जरूरत भर की चीजों के साथ रहना। कम में गुजारा करना। कुल मिलाकर, थोड़े में जीना यानी प्यार, सादगी और सुकून से जीना। जिंदगी भी तो यही है।

सफल एवं सार्थक जीवन के सादगी का दर्शन एवं जीवनशैली बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय सादगी दिवस हमारी जटिल दैनिक दिनचर्या की भागदौड़ से दूर रहने और जीवन में सरल चीजों की सराहना करने के लिए समर्पित है। हमारा जीवन तेजी से आगे बढ़ रहा है और व्यस्त होता जा रहा है। यह दिवस हमें बाहरी दुनिया से भीतर की ओर ले जाता है, जब हम एक कदम पीछे हटकर यह मूल्यांकन करते हैं कि हम कैसे जीवन को अधिक संतुलन बना सकते हैं, अव्यवस्था को दूर कर सकते हैं और खुद को अलग रख सकते हैं। आज तकनीक ने जितना हमारे जीवन को आसान बनाया है, उतना ही इसने हमें भटकाया भी है और जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा पैदा की है। एक साधारण जीवन को सोशल मीडिया पर शायद ही कभी सुर्खियों में लाया जाता है। जापान जैसे कुछ देशों में, लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया है कि अगर वे उन वस्तुओं से छुटकारा पा लें जो उनके किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं, तो उनका जीवन अधिक खुशहाल और कम तनावपूर्ण हो सकता है।

आप सुबह समय पर उठने की आदत डालें और व्यायाम, भ्रमण या योगा करने की आदत डालें। इसके लिए आप 10 मिनट से इसे करने की आदत डालें फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। पढ़ना आपके तनाव को कम कर सकता है। साथ ही यह आपकी शब्दावली का विस्तार भी करता है। मानसिक तनाव को दूर कर आपको सकारात्मक बनाता है। जब भी आप खाना लेकर बैठें तो टीवी ना देखें। पूरी तरह से खाने पर ध्यान लगाएं। फोन की आदत को धीरे धीरे कम करें। आज की तेज-रफ्तार दुनिया में, हम अक्सर खुद को ज्यादा की जरूरत में फंसा हुआ पाते हैं। अब समय आ गया है कि हम बुनियादी बातों पर वापस लौटें। जीवन को सरल बनाने का मतलब सिर्फ कम चीजें रखना नहीं है, यह उन चीजों के लिए जगह खोलता है जो हमें वास्तव में हमें खुशी देती हैं। यह धुंध को दूर करता है, दैनिक अव्यवस्था यानी अस्त-व्यस्तता को कम करता है, तनाव को कम करता है और खुशी को बढ़ाता है। थोरो का जन्मदिन हमें सादगी में आनंद खोजने और अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने के लिए एक कदम पीछे हटने के बारे में भी है। लोग तकनीक से दूर रहकर, प्रकृति का आनंद लेते हुए और अपने घरों को साफ करके जश्न मनाते हैं। इसका लक्ष्य उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है जो वास्तव में मायने रखती है, शांति और संतुष्टि को बढ़ावा देना।

एक से एक अच्छी छूट का विज्ञापन देखकर मन चीजें खरीदने को आतुर हो उठता है। जरूरत हो या ना हो, बस सस्ती और आकर्षक जानकर हम वस्तुएं खरीद डालते हैं। नतीजा, फालतू वस्तुओं का ढेर लग जाता है। मोटिवेशनल कोच ल्यूमिनिटा कहती हैं, 'हम कुछ भी खरीदें, पूरी गंभीरता से खरीदें। कम खरीदना, कम उपयोग करना और खुद को उन वस्तुओं के प्रति समर्पित करना ही सादगी से जीना है।' सादा जीवन यानी आजाद जीवन। वह जीवन, जो आपको उस ओर बढ़ने की राह दिखाता है, जहां जुनून और उपलब्धियां हैं। जहां ऐसा कोई शोर-शराबा या अव्यवस्था नहीं होती, जो आपके रास्ते की बाधा बन जाए। तब आप केवल वही साथ रखते हैं, जो बेहद जरूरी है। कुछ लोगों के लिए सादा जीवन बिताना बहुत कठिन हो सकता है। हमें यही सिखाया गया है कि चीजों का संचय ही सफलता की निशानी है। इससे हम अकसर अत्यंत तनाव में और अपने जीवन की बेतरतीबी में इस तरह फंस जाते हैं कि किसी उद्देश्य, सार्थकता और खुशी के साथ जीना दूभर हो जाता है। सादगी भरा जीवन आपको वैसा जीवन गढ़ने में मदद कर सकता है, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो संतोषप्रद और सार्थक होता है। बात चाहे भौतिक पदार्थों की उपलब्धि की हो या आध्यात्मिक उपलब्धि की, जीवन में लक्ष्य तथा संकल्प सबसे जरूरी हैं। सादगीपूर्ण जीवन आपको अपने लक्ष्य, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद करता है। हेनरी डेविड थोरो का मानना था कि सादगी से जीवन जीने से हम अधिक खुश, अधिक उत्पादक और अधिक संतुष्ट हो सकते हैं। विचारक और दार्शनिक सदियों से इस पर विचार करते रहे हैं। वे हमेशा सरल जीवन जीने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में सोचते रहे हैं, विशेषकर तब जब हमारी दुनिया अंतहीन समाचारों, प्रौद्योगिकी और कार्य की मांगों के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। यह उन चीजों को ना कहने के बारे में है जो मायने नहीं रखती हैं और उन चीजों को हाँ कहने के बारे में है जो मायने रखती हैं, जिससे आपका जीवन, परिवार और परिवेश खुशहाल बनता है। इस दृष्टिकोण के लिए जीवन के सभी पहलुओं के बारे में गहराई से सोचना जरूरी है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। थोरो का विचार कि एक साधारण जीवन खुशी की ओर ले जाता है, आज भी गूंजता एवं हमें प्रेरित करता है, हमें जीवन की अव्यवस्था को दूर करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है जो वास्तव में हमें खुशी देता है।

सेवा, संस्कार और संगठन का संगम, जेएसजी संवाद में गूंजा समाज निर्माण का संकल्प

कोटा | बिजनेस रेमेडीज

जैन सोश्यल ग्रुप्स इंटरनेशनल फेडरेशन, नॉर्दन रीजन जोन-6 के तत्वावधान में आयोजित 'संवाद' कार्यक्रम में फेडरेशन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बिरेन के. शाह के समक्ष कोटा संभाग के विभिन्न जैन सोश्यल ग्रुपों ने अपने सेवा कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम में जैन सोश्यल ग्रुप कोटा, मैत्री, चंबल सिटी, बूंदी, आगम, संगिनी फोरम कोटा तथा संगिनी फोरम चंबल सिटी के पदाधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में जोन कॉर्डिनेटर जोन 6 सुरेश जैन ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न ग्रुपों के अध्यक्षों ने अपने-अपने ग्रुप का परिचय देते हुए रक्तदान शिविर, वस्त्र वितरण, राजकीय विद्यालयों में सेवा कार्य तथा गौ सेवा जैसे प्रकल्पों की विस्तृत जानकारी अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखी। मुख्य अतिथि बिरेन के. शाह ने अपने संबोधन में फेडरेशन के प्रतिनिधित्व को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 5 नए ग्रुपों के गठन का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि फेडरेशन योग्य विद्यार्थियों को निःशुल्क एजुकेशन लोन प्रदान करता है, वहीं जेएसजी वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत किसी सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। उन्होंने जैन सोश्यल ग्रुप के विस्तार के लिए अधिकाधिक युवाओं को जोड़ने पर बल देते हुए कहा कि उनकी रुचि और इच्छा के अनुरूप प्रकल्प चलाकर उन्हें संगठन से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि फेडरेशन के स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व, 16 अगस्त को देशभर में रक्तदान अभियान चलाकर 50 हजार यूनिट रक्त एकत्रित किया जाएगा।

कार्यक्रम के संयोजक व फेडरेशन के पूर्व संयुक्त सचिव अनिल काला ने बताया कि जोन-6 में वर्तमान में 400 से अधिक दंपति सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विभिन्न ग्रुप विगत 25 वर्षों से निरंतर सक्रिय हैं और इन ग्रुपों के प्रतिभावान सदस्यों ने जिम्मेदारियां निभाते हुए नेतृत्व क्षमता विकसित की है। उन्होंने मांग रखी कि ऐसे योग्य सदस्यों को फेडरेशन व रीजन स्तर के पदों पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

फेडरेशन के पूर्व अंतराष्ट्रीय अध्यक्ष कमल संचेती ने अपने उद्बोधन में कोटा रीजन की फेडरेशन में मजबूत भागीदारी को दोहराते हुए कोटा की विभिन्न जेएसजी इकाइयों की सराहना की। उन्होंने कोटा और बूंदी के बाद झालावाड़, रावतभाटा तथा बांरा में भी ग्रुप विस्तार के प्रयास करने तथा वहां लोगों को संगठित करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम का संचालन अंजू कासलीवाल ने किया। नॉर्दन रीजन फेडरेशन के पूर्व वाइस चेयरमैन मनीष जैन अपने उद्बोधन में संगठन और कार्यकर्ताओं के आपसी विचारों के तालमेल पर प्रकाश डाला। मंच पर नॉर्दन रीजन के पदाधिकारी सुनील पहाड़िया, संगिनी को-ऑर्डिनेटर मोनिका जैन, जोन-3 की को-ऑर्डिनेटर रेणु लुहाड़िया तथा जोन-6 के को-ऑर्डिनेटर सुरेश जैन 'नगेदा' आसीन रहे।

प्रोपर्टी

बिज़नेस रेमेडीज

प्रकाशक एवं मुद्रक पुनीत जैन द्वारा सिंघवी पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के लिए आकाशदीप प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स सेक्टर नं.11, अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर-302020 जयपुर से मुद्रित एवं 217, सैकंड फ्लोर, ओके प्लस स्क्वायर, सेक्टर 7, मानसरोवर, जयपुर से प्रकाशित।

संपादक : पुनीत जैन
(पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)
मो. 9929106227
ई-मेल: remediesbusiness@gmail.com

डिसक्लेमर

बिज़नेस रेमेडीज़ का उद्देश्य अपने पाठकों को व्यापार और विकास से जुड़ी सटीक, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी प्रदान करना है। हम प्रकाशित सामग्री की विश्वसनीयता बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन किसी लेख में व्यक्त विचार हमेशा संपादकीय टीम की राय से मेल नहीं खा सकते। इसलिए पाठकों से निवेदन है कि किसी भी जानकारी पर आधारित निर्णय लेते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। प्रकाशित सामग्री के आधार पर लिए गए किसी निर्णय या कार्यवाही की जिम्मेदारी यह प्रकाशन नहीं लेता। इस प्रकाशन में दिखाए गए सभी विज्ञापन पूरी तरह से संपादकीय सामग्री से स्वतंत्र होते हैं। विज्ञापनों में किए गए दावों या दी गई जानकारी की पुष्टि या समर्थन बिज़नेस रेमेडीज़ द्वारा नहीं किया जाता। विज्ञापन से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत की पूरी ज़िम्मेदारी संबंधित विज्ञापनदाता की होगी। यहां प्रकाशित सभी लेख, रिपोर्ट और सामग्री चाहे वे स्टाफ लेखक, समाचार एजेंसियों या अतिथि लेखकों द्वारा दी गई हो, बिज़नेस रेमेडीज़ की बौद्धिक संपदा हैं। बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी सामग्री का दोबारा प्रकाशन, वितरण या प्रसारण करना कानूनन वर्जित है।

2047 तक अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान दस प्रतिशत तक बढ़ाना है: गजेंद्र सिंह शेखावत

नई दिल्ली | एजेंसी

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के योगदान को वर्तमान छह प्रतिशत से बढ़ाकर 2047 तक 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।

अंतरिम लक्ष्य के रूप में, केंद्र सरकार 2030 तक पर्यटन का हिस्सा सात प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का पर्यटन क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि घरेलू पर्यटन ने हाल के वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है।

पर्यटन को विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ सीधे स्थानीय समुदायों तक पहुंचें।

उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन, परिवहन, हस्तशिल्प, खाद्य एवं पेय पदार्थ और स्थानीय उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में

रोजगार और आय के अवसर पैदा करता है।

शेखावत ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि के बाद पर्यटन में सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। इसी के अनुरूप, केंद्र सरकार देश भर में पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने और पर्यटक सुविधाओं में सुधार करने को प्राथमिकता दे रही है।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी पहलों के कारण 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 2014 से भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुने से अधिक हो गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय और किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रभावी मुद्रास्फीति प्रबंधन से लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू पर्यटन में उल्लेखनीय उछाल आया है।

राजस्थान में तबादलों की प्रक्रिया से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में शेखावत ने कहा कि तबादलों पर लंबे समय से लगी रोक हटने के बाद कई कर्मचारियों ने पारिवारिक परिस्थितियों, स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य वास्तविक कठिनाइयों का हवाला देते हुए उनसे संपर्क किया।

उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय ने ऐसे आवेदनों को संबंधित मंत्रियों के समक्ष विचार के लिए भेज दिया है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, पात्र कर्मचारियों में से अधिकांश को तबादलों की प्रक्रिया का लाभ मिल चुका है।

हालांकि, कठिन तबादलों या अन्य प्रशासनिक कारणों से संबंधित मामलों में अभी भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने तबादलों की प्रि या को एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी।

सदस्यता कूपन

(केवल डाक या ई-मेल से प्राप्त करने के लिए)

अवधि	अंक	सदस्यता शुल्क
1 वर्ष	358	1050

E-mail
remediesbusiness@gmail.com

नामः .....

पताः .....

.....पिनकोड.....

फोनः..... मो. .....

ड्राफ्ट/चैक का विवरणः .....

ई-मेलः .....

बिजनेस रेमेडीज प्राप्त करने के लिए सदस्यता शुल्क बैंक अकाउंट में जमा कराये या सदस्यता फार्म भरकर चैक/डीडी के साथ कार्यालय पर भिजवायें।

Bank Account:- Business Remedies
A/c No. 61233949765 Bank Name: SBI

पताः- 217, सैकंड फ्लोर, ओके प्लस स्क्वायर, सेक्टर 7, मानसरोवर, जयपुर
फोनः- 9166611333, 9929106227

#साधारण डाक द्वारा बिजनेस रेमेडीज की डिलीवरी में अनियमितता होने पर बिजनेस रेमेडीज प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।

कोरियर सुविधा

कोरियर के द्वारा बिजनेस रेमेडीज मंगवाने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

बिना प्रॉपर्टी ब्रोकर के बुक करें बेस्ट फ्लैट, रियल्टी एक्सपर्ट ने बताए टिप्स

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज़

फ्लैट बुक करने वाले अधिकांश होम बायर्स प्रॉपर्टी ब्रोकर का सहारा लेते हैं। इसके एवज में ब्रोकर उनसे मोटा कमीशन लेते हैं। यह करोड़ों की प्रॉपर्टी में कई लाख रुपये तक होता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि बिना प्रॉपर्टी ब्रोकर के सहयोग के सही फ्लैट बुक नहीं किया जा सकता है। हमने इस सवाल का जवाब अंतरिक्ष इंडिया के सीएमडी और दिग्गज रियल्टी एक्सपर्ट राकेश यादव से जाना।

ब्रोकर के बिना इस तरह फ्लैट बुक करें

सबसे पहले अपना बजट तय करें : बिना प्रॉपर्टी ब्रोकर के अगर आप सही फ्लैट बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बजट निर्धारित करें। आप किस बजट का फ्लैट लेने में सक्षम हैं। उसके बाद डाउन पेमेंट और दूसरे लागत पर विचार करें।

मार्केट में रिसर्च करें : बजट तय करने के बाद आप अपने बजट के अंदर उपलब्ध प्रॉपर्टी में से बेस्ट प्रॉपर्टी चयन करने के लिए रिसर्च करें। यह आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करें। इसमें प्रॉपर्टी की कीमत, बाजार का ट्रेंड और इन्वेंट्री आदि की जानकारी जुटाएं।

अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी की पहचान करें : जब आपने एक बजट तय कर लिया है, अपने घर की खरीद के लिए शहर और एक प्रोजेक्ट का चयन करें। इसके बाद सीधे बिल्डर की सेल्स टीम से जुड़ें। प्रॉपर्टी की डिटेल्स और बिल्डर क्रेडेंशियल्स के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) की वेबसाइट से जानकारी सत्यापित करें।

प्रोजेक्ट का दौरा करें : प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट करने के बाद, वेबसाइटों पर दिए गए विवरण को जांच करने के बाद उस प्रोजेक्ट और फ्लैट को खुद से जाकर देखें। आस-पास के इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे या मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी को समझने के लिए, प्रोजेक्ट पर जाना बहुत जरूरी होता है। प्रोजेक्ट का फीडबैक और रेटिंग जानने के लिए बिल्डरों के सोशल मीडिया पेज और प्रॉपर्टी रेटिंग वेबसाइट देखें। अंत में, अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर शॉर्टलिस्ट की गई प्रॉपर्टी की रैंकिंग करें।

फाइनेंशियल फैसले लें : घर खरीदने के लिए होम लोन जरूरी है। आप होम लोन लेने के लिए सीधे बैंक या बिल्डर से बात कर सकते हैं। आजकल कई प्रोजेक्ट पहले से कई बैंकों द्वारा फंडेड होते हैं। वो आसानी से होम लोन दे देते हैं। आप बैंक से बातकर लोन के दस्तावेज तैयार करें।

दस्तावेज़ तैयार करें और समीक्षा करें : बिल्डर-बायर एग्रीमेंट, पेपर वर्क सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा करें। यह सुनिश्चित करते हुए कि बिक्री की शर्तों में कोई कैच नहीं है। इसके बाद बिल्डर से कीमत को लेकर मोलतोल करें।

डील फाइनल करें : बिल्डर से कीमत को लेकर मोलतोल फाइनल करने के बाद बैंक से लोन फाइनल करें। इसके बाद, आपको एक अलॉटमेंट लेटर पत्र प्राप्त होगा जिसमें उस फ्लैट का डिटेल्स जैसे कि फ्लैट नंबर, एरिया, एक्स्ट्रा चार्ज इत्यादि शामिल होंगे। इसको पढ़ने के बाद सेल एग्रीमेंट पर साइन करें। इसके बाद आप उस फ्लैट के आधिकारिक तौर पर मालिक हो जाएंगे। ऐसा कर आप अच्छी रकम बचा लेंगे।

BUSINESS

न्यूज ब्रीफ

रोटरी क्लब उदय ने संजीवनी नर्सिंग कॉलेज में लगाए पौधे

उदयपुर | बिजनेस रेमेडीज़

पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में रोटरी क्लब उदय ने संजीवनी नर्सिंग कॉलेज परिसर में 51 पौधों का वृक्षारोपण कर हरित भविष्य का संदेश दिया। क्लब के फाउंडेशन डायरेक्टर अशोक लिंजारा के संयोजन में आयोजित इस अभियान में रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण बागड़िया, पूनम बागड़िया तथा डीएसजी संजय कौशिक की गरिमामयी उपस्थिति रही। क्लब अध्यक्ष साक्षी डोडेजा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सदस्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे और उनके संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी निरंतर देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। फाउंडेशन डायरेक्टर अशोक लिंजारा ने बताया कि क्लब का हरित अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम में एडीएसजी रितु वैष्णव,चेयर राजेश चुघ, सचिव अनिकेत शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट अनीता मौर्य, जॉइंट सेक्रेटरी अशोक वीरवाल, धर्मेश डोडेजा, गोविंद यादव सहित रोटरी क्लब उदई के अनेक सदस्य तथा संजीवनी नर्सिंग कॉलेज के शिक्षक एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हुए अधिकाधिक वृक्षारोपण और उनकी सुरक्षा का संकल्प दोहराया।

चंबल गार्डन बनेगा राजस्थान का प्रमुख पर्यटन केंद्र, कोटा के विकास को मिलेगी नई गतिः लोकसभा अध्यक्ष बिरला

100 करोड़ की लागत से होगा चंबल गार्डन और किशोरपुरा मुक्ति धाम का पुनर्विकास

जयपुर | बिजनेस रेमेडीज़

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंबल गार्डन एवं किशोरपुरा मुक्ति धाम के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए कहा कि चंबल गार्डन हाड़ौती की विरासत और कोटा की पहचान है। लगभग पाँच दशक पहले विकसित इस ऐतिहासिक स्थल को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ नया स्वरूप दिया जाएगा, ताकि यह राजस्थान और देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी विशिष्ट पहचान बना सके। चंबल नदी का प्राकृतिक सौंदर्य, निकट स्थित भगवान शिव का प्राचीन धार्मिक स्थल भीतरिया कुंड और आधुनिक सुविधाएं मिलकर इसे पर्यटन का नया आकर्षण बनाएंगी। उन्होंने कहा कि दो वर्ष बाद यह गार्डन केवल कोटा ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल होगा। बिरला ने कहा कि कोटा के समग्र विकास का जो सपना हमने देखा था, वह अब तेजी से धरातल पर साकार हो रहा है। आने वाले वर्षों में हमारा कोटा शिक्षा के साथ-साथ खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी शहरों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। जिला स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, नेचुरल हेल्थ सिटी, योग एवं आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को भी विकसित किया जा रहा है। ट्रिपल आईटी का विस्तार, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि उत्पादों के

लिए प्रोसेसिंग प्लांट तथा खेल अधोसंरचना के विकास की योजनाएं क्षेत्र के युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर सृजित करेंगी।

कनेक्टिविटी में राजस्थान में बनेंगे सिरमौरः बिरला ने कहा कि आने वाले वर्षों में कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र प्रदेश के सबसे बेहतर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में शामिल होगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे, भोपाल मार्ग तथा अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार से क्षेत्र को नई गति मिलेगी। रेल संपर्क भी और मजबूत होगा तथा वर्ष 2027 तक एयर कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद कोटा देश के प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ जाएगा। चंबल गार्डन, चंबल रिवर फ्रंट, मुकुंदरा अभयारण्य, रामगढ़ अभयारण्य, संविधान पार्क, वैदिक पार्क तथा दिव्यांगजनों के लिए विकसित किए जाने वाले विशेष पार्क जैसे प्रकल्प कोटा और बूंदी को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान देंगे।

शासन-प्रशासन को पारदर्शी बनाएंगेः लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से नगर निगम, कोटा विकास प्राधिकरण तथा अन्य विभागों की कार्यप्रणाली को सरल बनाया जाएगा। अगले दो वर्षों में नई मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) लागू कर आमजन को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत देने और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के सुझाव और सहभागिता से ही बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। लोकतंत्र की यही शक्ति है कि हर मत का सम्मान हो। उन्होंने कोटा-बूंदी को देश का सबसे स्वच्छ, हराभरा तथा सबसे कम प्रदूषण वाला संसदीय क्षेत्र बनाने का आह्वान किया।

कोटा को मिलने जा रही नई पहचानः स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि लगभग 50 वर्ष पहले कोटा की पहचान बने चंबल गार्डन को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ नए स्वरूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का विजन केवल चंबल गार्डन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। इसी सोच के अनुरूप रिवर फ्रंट सहित शहर की अन्य पर्यटन परियोजनाओं को भी नई दिशा देने पर कार्य किया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से अधिकाधिक पर्यटक कोटा आएं और शहर राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान बना सके। खर्रा ने कहा कि कि लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व और कोटावासियों के सहयोग से आने वाले वर्षों में कोटा देश के प्रमुख पर्यटन, चिकित्सा और विकासशील शहरों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अलवर जिले में 24 करोड़ से अधिक राशि से बने राजकीय विद्यालयों के भवनों का किया लोकार्पण

जयपुर | बिजनेस रेमेडीज़

शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने अलवर के एक दिवसीय दौरे पर रहकर रैणी तहसील में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईशवाना के नव निर्मित भवन तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पिनान टाइप-3 के नव निर्मित भवन समेत कुल राशि 24.09 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 7 विद्यालयों के नव निर्मित भवनों का लोकार्पण किया एवं चिमरावली सिक्ख में राजकीय विद्यालय में सरस्वती प्रतिमा का अनावरण करने के साथ विभिन्न राजकीय विद्यालयों एवं गांवों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आयोजित कार्यक्रमों में अपने संबोधन में कहा कि मानवीय मूल्यों पर आधारित संस्कारित एवं नैतिकता युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कडी

में राज्य सरकार प्रदेश में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ-साथ बच्चों को पोषाहार, पाठ्य पुस्तकें, यूनिफार्म, साइकिल, स्कूटी, लेपटॉप, छात्रवृत्ति आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हित में एवं शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हेतु प्रदेश में पहली बार 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अब तक विद्यालयों में 20 प्रतिशत पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है। साथ ही पहली बार माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम मार्च में ही जारी किए गए हैं तथा पहली बार 1 अप्रैल को ही बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रूपये की राशि जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों को मरम्मत के लिए जारी की गई है।

राजस्थान के टेक्सटाइल निर्यात को वर्ष 2030 तक चार गुना करने का लक्ष्य

राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल गठित, पहली बार राज्य और जिला स्तरीय टेक्सटाइल निर्यात कार्ययोजना तैयार

जयपुर | बिजनेस रेमेडीज़

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन है कि प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए प्रत्येक सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे निवेश के साथ युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के समुचित अवसर मिल सकें। इसी मंशा के अनुसार उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा सेक्टर आधारित करीब 15 नई नीतियां लागू की गई हैं। अब राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति-2025 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है। साथ ही, राज्य में पहली बार राज्य का तथा 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया हैं। इसमें भारत सरकार द्वारा चयनित 7 चैंपियन जिले (अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर एवं कोटा) और 4 एसपाइरेशनल जिले (श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर एवं चूरू) शामिल हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि यह सेल राज्य में टेक्सटाइल इकाइयों को प्रोत्साहित करने, नवीनतम तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुआयामी प्रयास करेगी। इसमें औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर बाधाओं की पहचान, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों एवं निर्यातकों से संवाद, देश-विदेश के प्रमुख वस्त्र केंद्रों का अध्ययन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वस्त्र प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल है। साथ ही, टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित समग्र डेटा का संकलन एवं विश्लेषण करेगी। इसी वर्ष अक्टूबर में एक दो दिवसीय टेक्सटाइल समिट का आयोजन भी प्रस्तावित है। सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) के तहत टेक्सटाइल को थ्रस्ट क्षेत्र घोषित कर अतिरिक्त परिलाभ दिए जा रहे हैं।

सक्सेना ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक वस्त्र एवं परिधान निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान में भी इस क्षेत्र के निर्यात को 3-4 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कार्य भी शुरू कर दिया है। राजस्थान से कुल निर्यात वर्ष 2024-25 में 97, 171 करोड़ रुपये से अधिक था। इसमें टेक्सटाइल एवं इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों का हिस्सा करीब 13,500 करोड़ रुपये था, जो कुल निर्यात के 13 प्रतिशत से अधिक है। राजस्थान ऊन उत्पादन में प्रथम, कपास उत्पादन में पांचवें स्थान परः राजस्थान ऊन उत्पादन में लगभग 47 प्रतिशत योगदान के साथ प्रथम एवं कपास उत्पादन में पांचवें स्थान पर है। वर्तमान में प्रदेश में 1,800 से अधिक टेक्सटाइल और अपैरल यूनिट्स हैं। राजस्थान का वस्त्र उद्योग अपनी पारंपरिक तकनीकों, हैण्डब्लॉक प्रिंटिंग एवं विभिन्न वस्त्रों के लिए विश्वभर में अपनी एक विशिष्ठ पहचान रखता है। राज्य से विभिन्न टेक्सटाइल उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है एवं इस क्षेत्र में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं जिसके लिए वर्तमान सरकार लगातार प्रयासरत है।

सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकताः मंत्री दुर्गादास उइके

जयपुर | बिजनेस रेमेडीज़

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के राज्यमंत्री दुर्गादास उइके दो दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं अनुसंधान परिषद (टीआरआई) सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन सहित अन्य प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार

तक समयबद्ध रूप से पहुँचाने पर जोर दिया।

बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, लोकसभा सांसद डॉ. मन्नालाल रावत, समाजसेवी पुष्कर तेली सहित जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रारंभ में केंद्रीय मंत्री सहित अतिथियों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्जवलित कर बैठक का शुभारंभ किया। संभागीय आयुक्त एवं टीएडी आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, अतिरिक्त आयुक्त कृष्णपालसिंह चौहान, टीआरआई निदेशक ओपी जैन सहित अन्य ने अतिथियों का स्वागत किया। संभागीय आयुक्त केवलरमानी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनजाति उत्थान योजनाओं, टीएडी विभाग के नवाचारों तथा विभिन्न कार्य मों की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

केंद्रीय राज्यमंत्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुनिश्चित रूप से पहुँचे, जिससे जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन आए। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित मॉनिटरिंग तथा परिणामोन्मुख कार्यशैली अपनाने पर विशेष बल दिया।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी समन्वय से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, आधारभूत सुविधाओं और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने का आग्रह किया।

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर का किया निरीक्षण

जयपुर | बिजनेस रेमेडीज़

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर के प्रताप नगर में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अस्थाई परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं, प्रयोगशालाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्थाई परिसर में विद्यार्थियों की पढ़ाई और शोध कार्य के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, ताकि अकादमिक सत्र बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संचालित हो सके।

वी. श्रीनिवास ने प्रताप नगर स्थित इस अस्थाई परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्टक्चर से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य में फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में दक्ष विशेषज्ञों की मांग को देखते हुए इस संस्थान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। फॉरेंसिक विज्ञान में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। फोरेंसिक विज्ञान से आपराधिक जांच, साइबर सुरक्षा, अपराधियों की पहचान करने, साक्ष्य एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन और इसके स्थाई परिसर के निर्माण से जुड़े कार्यों के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर आत्माराम सावंत, राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त अरविंद कुमार पोसवाल, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर राखी अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एनएफएसयू के निदेशक प्रोफेसर एस. ओ.जुनारे, कार्यकारिणी कुल सचिव सी.डी.जुनेजा, अकादमिक निदेशक प्रोफेसर पूर्वी पोखरियाल, प्रशिक्षण एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध के निदेशक प्रोफेसर नवीन कुमार चौधरी वीसी के माध्यम से जुड़े।

ईर्ष्या

आपको चेहरा बदसूरत पसंद नहीं, कपड़े भी बेढंगे आप पसंद नहीं करेंगे और खाने के लिए प्लेट और चम्मच या थाली कटोरी ग्लास भी सुदर डिजाइन की पसंद करेंगे, घर भी हरा-भरा सजा हुआ, यूनिक, औरों से हटकर, दिव्य-भव्य महल सा हो, जिसे देख लोग कह उठे-क्या कहना, आभूषण भी खूबसूरत कलाकारी वाले लेंगे। दोस्ती के फील्ड में भी आपकी सोच ऐसी रहती है कि इसके संस्कार सुन्दर होने चाहिए। भावी पीढ़ी बच्चों के लिए भी सुन्दर बेहतरीन आइडिया वाली मनोभूमि की सावधानी रखते हो? यदि हां, तो ये मत भूलना की अमन चैन जहां रहना पसंद नहीं करते, गहने को फीका बना दें, पनपने का मौका क्यों दू। ईर्ष्या ऐसा धुन है जो जिंदगी को खोखला कर देता है। आपका चिंतन ऐसा हो कि उस शुभ चिंतन के धरातल पर कई उजड़े आशिया महक उठे। ईर्ष्या की आग और धुंआ संबंधों में सेंध लगाता है, आपके दामन में ईर्ष्या का दीमक धरन करे, उससे पहले आप वसधैव कुटुम्बकं की मौलिकता को पहचाने और आत्मवत् सर्व भूएसू को जिए।

चिंतनशीला वसुमति जी मा.सा।

पोस्टर प्रतियोगिता से दिया मातृ-शिशु स्वास्थ्य और जनसंख्या संतुलन का संदेश

उदयपुर | बिजनेस रेमेडीज़

रोटरेक्ट क्लब ऑफ ऐश्वर्या द्वारा जनसंख्या जागरूकता और रोटरी के 'मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य माह' के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय 'मातृ एवं शिशु देखभाल' रखा गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने मातृ स्वास्थ्य, शिशु देखभाल, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या संतुलन जैसे विषयों पर आकर्षक और संदेशपरक पोस्टर तैयार

किए। इन पोस्टरों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्वस्थ माताएं, सुरक्षित बचपन और बेहतर स्वास्थय सुविधाएं ही सशक्त परिवार एवं समृद्ध समाज की नींव हैं।

क्लब की अध्यक्ष रोटरेक्टर हर्षा मारवाल ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए युवाओं में जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित करना आवश्यक है। इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों को समझने और उनके समाधान के प्रति जिम्मेदार सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं।

क्लब की सचिव रोटरेक्टर नितीशा महावर ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सीधे तौर पर परिवार और समाज के समग्र विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता ही किसी भी सकारात्मक परिवर्तन की पहली सीढ़ी है और ऐसे आयोजन लोगों को स्वास्थय एवं परिवार नियोजन के महत्व से जोड़ने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम में क्लब के अन्य सदस्यों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई तथा प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर निरंतर रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

आवश्यकता

बिज़नेस रेमेडीज दैनिक समाचार पत्र को कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली में खबरों एवं विज्ञापन कार्य हेतु प्रतिनिधि की आवश्यकता है

सम्पर्क करें

बिज़नेस रेमेडीज

217, सैकंड फ्लोर, ओके प्लस स्क्वायर, सेक्टर 7, मानसरोवर, जयपुर

फोनः +91-9929106227

ई-मेलः remediesbusiness@gmail.com

रुपए में स्थिरता लाने के लिए उठाए गए सरकारी कदमों के बाद एफआईआई निवेश में हुई बढ़ोतरी : एसबीआई रिसर्च

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

सरकार द्वारा पिछले महीने और ज्यादा विदेशी फंड आकर्षित करने और रुपए में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के उपाय घोषित किए जाने के बाद भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 7 अरब डॉलर निवेश किए हैं। यह जानकारी एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में दी गई। इस दौरान 20 मई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.8 के निचले स्तर से भारतीय रुपए जून के आखिर तक करीब 2.2 प्रतिशत की मजबूती आई है। पिछले महीने, मध्य पूर्व में चल रहे तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने विदेशी निवेश और रुपए की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए। इन उपायों में सॉवरेन बॉन्ड पर एफआईआई और एफपीआई को टैक्स से छूट, एफसीएनआर(बी) डिपॉजिट के लिए सब्सिडी वाली हेजिंग लागत और पीएसयू लोन के लिए रियायती डॉलर-स्वैप सुविधा शामिल है। हालांकि, हालिया भू-राजनीतिक तनाव ने एक्सचेंज रेट पर फिर से दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका-ईरान सीजफायर खत्म करने की घोषणा के बाद ये तनाव और बढ़ गए, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत में उछाल आया और रुपए की कीमत में गिरावट हुई। इसके बावजूद, आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, अब इंडियन बास्केट के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल या उससे कम रहने की उम्मीद है। इससे तेल आयात बिल में कम से कम 30 से 35 अरब की बचत होगी, जबकि पहले के अनुमान में तेल की कीमत 130 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई थी। इस बीच, दो हफ्तों के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.4 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जबकि वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में कमर्शियल पेपर (सीपी) जारी करने और बैंक `डिट में बढ़ोतरी देखी गई। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में सीपी जारी करने में तेजी आई और जून में जारी किए गए सीपी 55 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। वहीं, वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में बैंक क्रेडिट बढ़कर 5.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 2.4 लाख करोड़ रुपए था। एसबीआई रिसर्च के अनुसार, जिन सेक्टर में सबसे अधिक कमर्शियल पेपर जारी किए गए, उनमें बैंक क्रेडिट ग्रोथ भी मजबूत रही और वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में नए प्रोजेक्ट की घोषणाओं में उनकी हिस्सेदारी लगभग 69 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) के जरिए फंड जुटा रहे थे। हालांकि, अब इस ट्रेंड के बदलने की उम्मीद है। इसके अलावा, 30 जून को खत्म हुए दो हफ्तों के दौरान रिकॉर्ड 7 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट बढ़ोतरी के कारण लिक्विडिटी की स्थिति और बेहतर होने की संभावना है।

हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट फंड्स का एसआईएफ एयूएम में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा

नई दिल्ली | एजेंसी

हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट फंड्स का स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (एसआईएफ) के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में 67 प्रतिशत हिस्सा रहा। इन फंड्स का योगदान कुल 17,858 करोड़ रुपये के एसआईएफ एयूएम में 11,910 करोड़ रुपये रहा। यह जानकारी वैल्यूमैट्रिक्स की रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट फंड्स का औसत फोलियो आकार 35 लाख रुपये रहा। हाइब्रिड निवेश रणनीतियों का कुल एसआईएफ एयूएम में 72 प्रतिशत हिस्सा रहा, जो 12,822 करोड़ रुपये के बराबर है। इनका औसत फोलियो आकार 32.7 लाख रुपये दर्ज किया गया। जून 2026 में एसआईएफ में कुल निवेश प्रवाह 3,782 करोड़ रुपये रहा, जो मई 2026 के 1,396 करोड़ रुपये की तुलना में 171 प्रतिशत अधिक है। अक्टूबर 2024 से अब तक एसआईएफ में संचयी निवेश प्रवाह 17,407 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इक्विटी आधारित रणनीतियों का कुल एयूएम में 28 प्रतिशत हिस्सा रहा, जो 5,036 करोड़ रुपये के बराबर है। इनका औसत फोलियो आकार 14.1 लाख रुपये रहा। रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून 2026 तक कुल एसआईएफ एयूएम 17,858 करोड़ रुपये रहा, जबकि औसत फोलियो आकार 23.8 लाख रुपये दर्ज किया गया। जून में हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट फंड्स में 2,043 करोड़ रुपये का निवेश आया, जो मई की तुलना में 189 प्रतिशत अधिक है। अक्टूबर 2024 से अब तक इन फंड्स में कुल 11,568 करोड़ रुपये का निवेश आया है, जो कुल एसआईएफ निवेश प्रवाह का 66 प्रतिशत है। इक्विटी आधारित रणनीतियों में जून के दौरान 1,097 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो मासिक आधार पर 68 प्रतिशत अधिक है। अक्टूबर 2024 से इन रणनीतियों में कुल 4,938 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2026 में म्यूचुअल फंड उद्योग में निवेशकों की भागीदारी मजबूत बनी रही। कुल म्यूचुअल फंड एयूएम बढ़कर 82.2 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि सक्रिय इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स में शुद्ध निवेश लगभग 36,000 करोड़ रुपये रहा।

मार्केट आउटलुक

पहली तिमाही के नतीजे, कच्चे तेल और ईरान-अमेरिका युद्ध से तय होगी शेयर बाजार की चाल

मुंबई | एजेंसी

भारतीय शेयर बाजार के लिए ये सप्ताह काफी अहम रहने वाला है। इस दौरान वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के नतीजे, कच्चे तेल की चाल, ईरान-अमेरिका युद्ध और महंगाई के आंकड़े बाजार की दिशा तय करेंगे। 13-17 जुलाई के आगामी सत्र में बजाज कंज्यूमर, एचसीएल टेक, एलटीटीएस, टाटा इलेक्सी, एंजेलवन, एचडीएफसीएएमसी, एचजीएफसीलाइफ, नेटवर्क18, यूनियन बैंक, 360वन, डीबीकॉर्प,पॉलीकैप, जियोफोन, फेडरलबैंक, जेएसडब्ल्यूस्टील, आरबीएलबैंक, टाटाटेक, आईसीआईसीआईबैंक, एचडीएफसी बैंक, जेकेसीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए जाएंगे। सरकार की ओर से 13 जुलाई को खुदरा महंगाई का डेटा जारी किया जाएगा।

महंगाई डेटा बाजार के लिए काफी अहम होता है और इससे देश में मांग और आपूर्ति की स्थिति की पूरी जानकारी मिलती है। इसके अलावा, ईरान-अमेरिका युद्ध से जुड़े अपडेट भी बाजार के लिए अहम होने वाले हैं। अमेरिका ने शनिवार देर रात ईरान पर बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक की है। वहीं, अमेरिकी सेना ने करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।

अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने यह हमला होर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हुए हमले के जवाब में किया था, जिससे जहाज को भारी क्षति पहुंची और इंजन को नुकसान हुआ। होर्मुज से दुनिया के कुल 20 प्रतिशत कच्चे तेल का निर्यात होता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता मिलाजुला रहा। इस दौरान सेंसेक्स 194 अंक या 0.25 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 77,569 और निफ्टी 64 अंक या 0.26 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,207 पर बंद हुआ। इस दौरान मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 846 अंक या 1.36 प्रतिशत की मजबूती के साथ 63,036 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 241 अंक या 1.26 प्रतिशत की तेजी के साथ 19,416 पर था। समीक्षा अवधि में सूचकांकों में सबसे अधिक तेजी निफ्टी रियल्टी (5.37 प्रतिशत) और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (3.74 प्रतिशत) में देखी गई। निफ्टी आईटी (2.08 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (0.72 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (0.52 प्रतिशत) और निफ्टी सर्विसेज (0.30 प्रतिशत) की तेजी के साथ सबसे ज्यादा बढ़ने वाले सूचकांक थे।

निफ्टी मीडिया (1.85 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (1.57 प्रतिशत), निफ्टी पीएसई (1.01 प्रतिशत), निफ्टी इंडिया डिफेंस (0.93 प्रतिशत) और निफ्टी हेल्थकेयर (0.63 प्रतिशत) की कमजोरी के साथ लाल निशान में बंद हुए।

एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड ने 902 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया

मुंबई | एजेंसी

एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड (एलटीएफ), भारत की अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में से एक, ने 30 जून 2026 को समाप्त पहली तिमाही के लिए 902 करोड़ रुपये का समेकित कर पश्चात लाभ दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 29 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि के दौरान एलटीएफ की समेकित बुक 27 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,29,634 करोड़ रुपये तक पहुँच गई, जो कंपनी का अब तक का सर्वाधिक स्तर है।

वित्तीय परिणामों पर टिप्पणी करते हुए एलएंडटी फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री सुदीप्तारॉयने कहा, 'वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में भी हमने बदलते मैक्रोइकोनॉमिक माहौल–जिसमें भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ, महँगाई का दबाव और ऊँची उधार लागत शामिल हैं–के बीच अनुशासित निष्पादन पर ही ध्यान केंद्रित रखा। इन बाहरी चुनौतियों के बावजूद हमारी विविध रिटेल फ्रेंचाइज़ी ने मजबूती दिखाई और 'लक्ष्य 31' स्ट्रेटेजिक प्लान के अनुरूप मजबूत बिजनेस मोमेंटम और स्वस्थ बुक ग्रोथ दर्ज की।'

तिमाही के दौरान रिटेल बुक का आकार 1,27,535 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सालाना 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने 30 जून 2026 को समाप्त पहली तिमाही के लिए 23,852 करोड़ रुपये का मजबूत रिटेल वितरण दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 36 प्रतिशत अधिक है। एलटीएफ खुद को एआई-नेटिव ऋणदाता में बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग को लगातार तेज कर रही है। कंपनी का ग्राहक-उन्मुख 'प्लैनेट' ऐप ग्राहकों के लिए एक सशक्त डिजिटल चैनल के रूप में उभरा है। 30 जून 2026 तक इस ऐप के 2.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं, जिनमें से 20 लाख से अधिक ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इसी तारीख तक इस चैनल के माध्यम से 14 करोड़ से अधिक रिक्वेस्ट सर्विस की गई हैं, 11,500 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन हुआ है और लगभग 34,462 करोड़ रुपये के लोन सोर्स किए गए हैं।

आरईसी ने त्रिपुरा में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किए समझौते

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरईसी लिमिटेड ने त्रिपुरा सरकार के साथ बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपये तक के वित्तपोषण किए जाने के मकसद से दो शुरुआती समझौते किए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ये समझौते 'डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026' के दौरान किए गए।

समझौतों का मकसद पूर्वोत्तर क्षेत्र में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना और बिजली अवसंरचना को मजबूत करना है। आरईसी लिमिटेड ने पहले एमओयू में त्रिपुरा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (टीआरईडीए) के साथ साझेदारी की है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, आरईसी लिमिटेड ने त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (टीएसईसीएल) के माध्यम से राज्य सरकार के बिजली विभाग के साथ भी एक अन्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत राज्य के बिजली क्षेत्र की 10,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, बिजली अवसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण को गति देना तथा राज्य के नागरिकों को विश्वसनीय तथा टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

नुवोको विस्टास ने सूरत के लिमला संयंत्र में 20 लाख टन क्षमता शुरू की

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

नुवोको विस्टास ने गुजरात के सूरत स्थित लिमला सीमेंट संयंत्र में 20 लाख टन प्रति वर्ष की ग्राइंडिंग क्षमता की शुरुआत की घोषणा की। निरमा समूह की कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसके पूर्ण-स्वामित्व वाली इकाई वदराज सीमेंट लिमिटेड (वीसीएल) ने 11 जुलाई, 2026 को इस नई क्षमता की शुरुआत की। नुवोको विस्टास ने एक साल पहले कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत करीब 1,800 करोड़ रुपये में कर्जग्रस्त कंपनी वीसीएल का अधिग्रहण किया था।

ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद, भारतीय शेयर बाजार में तेजी है

दिनांक 10.07.2026 पर निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ 24249 पॉइंट पर :-

अगले कारोबार के लिए संभवित निफ्टी फ्यूचर 24088 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर 24303 - 24404 अंक को छू सकता है निफ्टी फ्यूचर में प्रतिक्रियात्मक के लिए 24008 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थिति....!!!

अब नजर डालते हैं फ्यूचर्स स्टॉक सम्बंधित मूवमेंट पर...!!

हिंदाल्को इंडस्ट्रीज (977) :- मेटल एवं एल्युमिनियम सेक्टर की इस अग्रणी कंपनी के शेयर की कीमत फिलहाल 944 रुपये के आसपास है। 930 रुपये के सख्त स्टॉपलॉस के साथ यह स्टॉक 989 से 1003 रुपये के आसपास इस शेयर का मूल्य स्तर दर्ज होने की संभावना है...!! 1008 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!

इंडियन बैंक (806) :- तकनीकी चार्ट के अनुसार पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर का यह स्टॉक 787 रुपये के आसपास सकारात्मक ब्रेकआउट!! 776 रुपये के सपोर्ट से खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक 823 रुपये से 830 रुपये के आसपास मूल्य स्तर दर्ज करने की संभावना है...!!

कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) (788) :- रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट सर्विसेज सेक्टर के शेयर में 797 रुपये से 808 रुपये तक की शॉर्ट टर्म तेजी का रुख दिखाएगा, 767 रुपये के अनुमानित सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!

डीएलएफ (682) :- रियल एस्टेट सेक्टर के शेयर में 696 रुपये से 707 रुपये तक की शॉर्ट टर्म तेजी का रुख दिखाएगा, 664 रुपये के अनुमानित सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!

निखिल भट्ट
(इन्वेस्टमेंट पॉईंट)

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (550) :- 01 रुपये के फेसवैल्यू वाला फंडामेंटली मजबूत यह स्टॉक करीब 518 रुपये स्टॉप लॉस के साथ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के इस स्टॉक में लगभग 567 रुपये से 580 रुपये तक लक्ष्य की संभावना रखता हैज!!!

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस (508) :- तकनीकी चार्ट के अनुसार इंश्योरेंस सेक्टर के इस शेयर पर खरीदारी होने की संभावना के साथ 533 रुपये से 540 रुपये के आसपास मूल्य स्तर दर्ज होने की संभावना है। प्रतिक्रियात्मक ट्रेडिंग के लिए 488 रुपये का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!

वरुण बेवरेजेस (481) :- इस शेयर को 467 रुपये के आसपास मजबूत सपोर्ट दर्ज करते हुए खरीदारी की संभावना के साथ इसकी कीमत 493 रुपये से 500 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास रहने की संभावना है...!!! 510 रुपये के स्तर पर तेजी का माहौल..!!

अंबुजा सीमेंट्स (437) :- सीमेंट सेक्टर का यह स्टॉक 397 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ खरीदकर 454 रुपये से 460 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास रहने की संभावना है...!!

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (398) :- ऑयल एवं गैस सेक्टर के इस शेयर को करीब 370 रुपये स्टॉपलॉस के साथ खरीदकर 408 रुपये से 419 रुपये का मूल्य स्तर दर्ज होने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 378 रुपये के सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!

बीपीसीएल (312) :- नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इस शेयर को करीब 280 रुपये स्टॉपलॉस के साथ खरीदकर 323 रुपये से 330 रुपये का मूल्य स्तर दर्ज होने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 294 रुपये के सख्त स्टॉपलॉस का पालन करेंज!!

नोटः शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशको को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए।

ओएनजीसी ने लद्दाख में दूसरे भू-तापीय कुएं की ड्रिलिंग पूरी की

नई दिल्ली | एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने लद्दाख की पुगा घाटी में अपने दूसरे भू-तापीय कुएं की ड्रिलिंग पूरी कर ली है। यह भारत के पहले पायलट भू-तापीय बिजली संयंत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ओएनजीसी की अनुसंधान एवं विकास इकाई ओएनजीसी एनर्जी सेंटर ने लगभग एक महीने में 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 1,000 मीटर गहराई तक इस कुएं की ड्रिलिंग की। ओएनजीसी के बयान के अनुसार, यह कार्य पहले जियोथर्मल (भू-तापीय) ड्रिलिंग अभियान की तुलना में कम समय और कम लागत में पूरा किया गया। कंपनी के अनुसार, यह नया कुआं पुगा में खोदे गए पहले भू-तापीय कुएं की सफलता पर आधारित है।

पहले कुएं से पानी के उबलने के तापमान से अधिक तापमान वाली भाप निकली थी, जिससे इस क्षेत्र में भू-तापीय ऊर्जा की अपार संभावनाओं की पुष्टि हुई थी। ओएनजीसी ने कहा कि दूसरा कुआं भारत के पहले 1 मेगावाट इलेक्ट्रिक (एमडब्ल्यूई) पायलट भू-तापीय बिजली संयंत्र के विकास में मदद करेगा और देश में भू-तापीय ऊर्जा के व्यावसायिक उपयोग का मार्ग खोल सकता है। परियोजना के अगले चरण में 1 मेगावाट क्षमता वाला पायलट जियोथर्मल बिजली संयंत्र स्थापित करने और दीर्घकाल में लद्दाख को विश्वसनीय आधारभूत बिजली उपलब्ध कराने के लिए भू-तापीय संसाधनों का विकास करने की योजना है। पूर्वी लद्दाख में स्थित पुगा भू-तापीय क्षेत्र को भारत का सबसे संभावनाशील भू-तापीय संसाधन माना जाता है। भू-तापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद प्राकृतिक गर्मी का उपयोग करके बिजली उत्पादन और ताप उपलब्ध कराती है। यह कम-कार्बन उत्सर्जन वाली चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने वाली ऊर्जा का स्रोत है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, यह मौसम पर कम निर्भर होने के कारण अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। हालांकि, पुगा क्षेत्र को लंबे समय से भारत का सबसे संभावनाशील भू-तापीय क्षेत्र माना जाता रहा है और यहां समय-समय पर खोज संबंधी कार्य भी किए गए हैं, लेकिन तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों के कारण अब तक व्यावसायिक स्तर पर जियोथर्मल बिजली उत्पादन शुरू नहीं हो सका है।

इस बीच, भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता 2014 के 81 गीगावाट से बढ़कर वर्तमान में 288 गीगावाट हो गई है, जो 256 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाती है। इसी अवधि में सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट और पवन ऊर्जा क्षमता 21 गीगावाट से बढ़कर 56.4 गीगावाट हो गई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर भारत के हाउसिंग मार्केट को दे रहे हैं गति, कोलकाता, नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने परिपक्व महानगरों को पीछे छोड़ा : मैजिकब्रिक्स प्रॉपइंडेक्स रिपोर्ट

नई दिल्ली | एजेंसी

भारत का आवासीय बाजार एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां सिर्फ महानगरीय दर्जा नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, किफायती दरें और कनेक्टिविटी यह तय कर रहे हैं कि आवासीय मांग कहां बढ़ रही है। मैजिकब्रिक्स प्रॉपइंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 के बीच आवासीय मांग तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर 1.2 प्रतिशत घटी है। हालांकि, कोलकाता, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पुणे ने लगातार मजबूत होमबायर रुचि आकर्षित की, जो एक तेजी से चयनात्मक होते हाउसिंग बाजार का संकेत है।

रिपोर्ट में शामिल 13 शहरों में से, कोलकाता ने सबसे मजबूत मांग वृद्धि दर्ज की, जो 7.5 प्रतिशत QoQ रही, इसके बाद नोएडा (5.5 प्रतिशत), ग्रेटर नोएडा (4.1 प्रतिशत) और पुणे (2.1प्रतिशत) का स्थान रहा। इसके विपरीत, हैदराबाद (-6प्रतिशत), चेन्नई (-5.8 प्रतिशत), नई दिल्ली (-2.9प्रतिशत) और बेंगलुरु (-1.8 प्रतिशत) सहित कई स्थापित महानगरीय बाजारों में मांग में नरमी देखी गई, जबकि मुंबई (+0.6 प्रतिशत) कमोबेश स्थिर बना रहा। यह रुझान दर्शाता है कि होमबायर्स तेजी से उन बाजारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो किफायती दरों, कनेक्टिविटी, आवास विकल्प और दीर्घकालिक मूल्य का बेहतर संतुलन प्रदान करते हैं। आपूर्ति पक्ष में भी यह उभरता विभाजन झलकता है। राष्ट्रीय आवासीय आपूर्ति में 1.2 प्रतिशत QoQ की वृद्धि हुई, जिसमें बेंगलुरु (+3.7त्न), गुरुग्राम (+3.1त्न), हैदराबाद (+2.9त्न) और कोलकाता (+1.7त्न) सबसे आगे रहे। हालांकि, नोएडा (-0.6 प्रतिशत) और पुणे (-0.9 प्रतिशत) में देश की सबसे मजबूत मांग वृद्धि दर्ज करने के बावजूद अपेक्षाकृत कम आपूर्ति वृद्धि देखी गई, जो स्वस्थ इन्वेंट्री अवशोषण और बेहतर होते बाजार बुनियादी सिद्धांतों का संकेत है।

पूरे भारत में आवासीय कीमतें मजबूत बनी रहीं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर 1 प्रतिशत QoQ की वृद्धि हुई। ग्रेटर नोएडा भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ता प्रमुख आवासीय बाजार बनकर उभरा, जिसने 1.9 प्रतिशत QoQ मूल्य वृद्धि दर्ज की, जो यह दर्शाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किस तरह मजबूत आवासीय मांग और पूंजी वृद्धि में तब्दील हो रहे हैं। कोलकाता में 1 प्रतिशत QoQ की स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई, जबकि नोएडा और पुणे ने बढ़ती खरीदार मांग के बावजूद स्थिर कीमतें बनाए रखीं, जो उनकी किफायती दरों के लाभ को और मजबूत करता है। इस बीच, हैदराबाद (+2.4 प्रतिशत), बेंगलुरु (+1.9 प्रतिशत) और गुरुग्राम (+1.8 प्रतिशत) में मांग में नरमी के बावजूद कीमतों में वृद्धि जारी रही, जो इन बाजारों में डेवलपर्स के निरंतर दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाता है।

प्रसून कुमार, सीएमओ, मैजिकब्रिक्स, ने कहा कि भारत का आवासीय बाजार अब चक्रीय होने के बजाय तेजी से चयनात्मक होता जा रहा है। आज के होमबायर्स शहरों जितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को भी चुन रहे हैं। मजबूत कनेक्टिविटी, रोजगार के अवसरों और किफायती आवास वाले बाजार अधिक खरीदार रुचि आकर्षित कर रहे हैं, भले ही समग्र बाजार गतिविधि में नरमी आ रही हो। ग्रेटर नोएडा इस बदलाव का उदाहरण है। आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और विस्तारित एक्सप्रेसवे नेटवर्क के साथ, यह क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के विस्तार मात्र के बजाय एक आत्मनिर्भर आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित हो रहा है। जैसे-जैसे यह रुझान मजबूत होगा, आवासीय वृद्धि उन बाजारों में तेजी से केंद्रित होती जाएगी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर रोजमर्रा की रहने योग्यता और दीर्घकालिक आर्थिक अवसर में तब्दील होता है। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2 बीएचके घरों की मांग में 42 प्रतिशत हिस्सेदारी रही, इसके बाद 3 बीएचके घरों की 37 प्रतिशत हिस्सेदारी रही, जो मिलकर खरीदार रुचि का लगभग 79त्न हिस्सा बनाते हैं। आपूर्ति पक्ष में, डेवलपर्स ने बड़े घरों को प्राथमिकता देना जारी रखा, जिसमें उपलब्ध इन्वेंट्री में 3 बीएचके यूनिट्स की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत रही।

'भारत का मजबूत आर्थिक आधार और रुपए की स्थिरता एफपीआई निवेश को वापस लाने में कर रही है मदद'

नई दिल्ली | एजेंसी

सरकार की ओर से डेट निवेश के टैक्स नियमों में किए गए बदलाव विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही रुपए की स्थिरता भी विदेशी प्रवाह को वापस लाने में मदद कर रही है। यह जानकारी एक्सपर्ट्स की ओर से दी गई। एक्सपर्ट्स ने आगे कहा कि इन्हीं कारणों के चलते जुलाई की शुरुआत में विदेशी निवेशक खरीदार बन गए थे। एक से लेकर 10 जुलाई तक एफपीआई ने 5,155 करोड़ रुपए का निवेश किया।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वी.के. विजयकुमार ने कहा, 'इसके अलावा, 'प्राइमरी मार्केट और अन्य' कैटेगरी के जरिए 10,001 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे इस दौरान कुल निवेश 15,156 करोड़ रुपए हो गया है। यह एक सकारात्मक खबर है।' भारत में एफपीआई निवेश में एक अहम ट्रेंड डेट की हिस्सेदारी का लगातार बढ़ना है।

जुलाई में अब तक, एफपीआई ने 'जनरल लिमिट' के जरिए 3,228 करोड़ रुपए और 'फुली एक्सेसिबल रूट' (एफएआर) के जरिए 6,619 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के बेहतर होते मैक्रो-इकोनॉमिक हालात और रुपए में स्थिरता ने एफपीआई निवेश के इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। चिप ट्रेड में कमजोरी और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों में एफपीआई का बिकवाली करने से भी भारत में निवेश बढ़ा है। बाजार पर नजर रखने वालों का कहना है कि जब तक पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक हालात और खराब नहीं होते, तब तक यह ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। पिछले हफ्ते, पश्चिम एशिया में फिर से बढ़े भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण बाजार में चार हफ्ते से चली आ रही बढ़त का सिलसिला टूट गया और बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।

इस हफ्ते बाजार के मूड पर भू-राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे ज्यादा असर रहा। हाल ही में अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान द्वारा खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की खबरों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के रिसर्च एसवीपी अजीत मिश्रा ने कहा, ÷इस नए टकराव के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें कुछ समय के लिए 80 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से ऊपर चली गईं, लेकिन हफ्ते के अंत तक ये 76 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गईं, जिससे आयातित महंगाई और बाहरी सेक्टर के जोखिमों को लेकर कुछ चिंताएं कम हुईं।

पीएमएफएमई योजना के तहत क्रेडिट-लिंक्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के लाभार्थियों की संख्या 2 लाख के पार पहुंची

नई दिल्ली | एजेंसी

केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना' (पीएमएफएमई) के तहत दो लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को लोन मंजूर किए जा चुके हैं।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि 2 लाख लोन मंजूरी का आंकड़ा पार करते हुए इस स्कीम ने 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट जुटाया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 90 प्रतिशत लाभार्थी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और 44 प्रतिशत महिला उद्यमी हैं। साथ ही, पीएमएफएमई से मदद पाने वाले 75,000 से ज्यादा उद्यम उद्यम आधार, उद्यम असिस्ट, एफएसएसएआई और जीएसटी जैसे रजिस्ट्रेशन के जरिए औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कीम ने लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।

पासवान ने कहा कि दो लाख लाभार्थियों की उपलब्धि 'यह दिखाती है कि यह विजन पूरे देश में मापने योग्य नतीजों में बदल रहा है।' उन्होंने सभी लाभार्थियों में महिला उद्यमियों की लगभग 44 प्रतिशत भागीदारी को 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की सच्ची भावना और विकसित भारत की आधारशिला' बताया। मंत्री ने स्कीम के तहत मिलने वाली 'सीड कैपिटल' मदद पर भी जोर दिया, जिसके तहत 4.18 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों की मदद की गई है। साथ ही, मंत्रालय के 80 कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर के नेटवर्क को 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मंजूरी दी गई है, जिनमें से 32 शुरू हो चुके हैं। इस स्कीम के तहत 1.76 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें से 77 प्रतिशत महिलाएं हैं। एमओएफपीआई के संयुक्त सचिव देवेश देवल ने देशव्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा करते हुए पीएमएफएमई स्कीम के महत्व को बताया। यह स्कीम माइक्रो-फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों को वित्तीय मदद, ट्रेनिंग, हैंडहोल्डिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से लेकर मार्केट लिंकेज तक हर तरह की मदद देती है।

अफगान कृषि मंत्री की भारत यात्रा, खेती-किसानी से लेकर जल संरक्षण में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर रहा जोर

नई दिल्ली | एजेंसी

अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुधन मंत्री मावालावी अताउल्लाह ओमरी ने 7 से 12 जुलाई 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार अक्टूबर 2025 के बाद अफगानिस्तान से भारत की यह चौथी मंत्री-स्तरीय यात्रा थी, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संपर्क और सहयोग को दर्शाती है।

एमईए ने इस यात्रा के दौरान हुई अहम चर्चाओं और बैठकों को लेकर बयान जारी किया। बताया कि यात्रा के दौरान अफगान मंत्री ने केंद्रीय कृषि

एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने कृषि, सिंचाई, पशुधन विकास, कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण और कृषि व्यापार के क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग की समीक्षा की तथा भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। वार्ता में खाद्य सुरक्षा, बेहतर बीज प्रणाली और फसल उत्पादकता बढ़ाने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। भारत ने अफगानिस्तान के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अपना समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने वाली फसल किस्मों, जैव-सशक्त फसलों, टिकाऊ सिंचाई तकनीकों, जल संरक्षण और जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। अफगान कृषि मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कृषि और खाद्य उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण पर चर्चा हुई। इसके अलावा अफगान प्रतिनिधिमंडल ने विदेश राज्य मंत्री एवं कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा से मुलाकात कर अफगान जनता के विकास और कल्याण से जुड़े द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारत के प्रमुख कृषि और अनुसंधान संस्थानों के साथ भी संवाद किया। इनमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र (सीआईएमएमवाईटी), अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी), अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी), अंतरराष्ट्रीय उर्वरक विकास केंद्र (आईएफडीसी), फिक्की और पीएचडीसीसीआई शामिल रहे।

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में नए उद्योग लगाने के लिए सीधी जमीन खरीद नीति की घोषणा की

कोलकाता | एजेंसी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा भूस्वामियों से सीधे जमीन खरीदने की नीति की घोषणा की।

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने हुगली जिले के डंकुनी में एक होजरी निर्माण इकाई के शिलान्यास समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि हमने सीधे भूमि खरीद की नीति तैयार कर ली है। राज्य सरकार ने पहले ही राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सीधे भूमि खरीद की नीति शुरू कर दी थी और फिर उन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को कांटेदार बाड़ लगाने के लिए सौंप दिया था। उद्योग के मामले में भी यही नीति अपनाई जाएगी। हम नहीं चाहते कि उद्योग के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर वैसा तनाव फिर से पैदा हो, जैसा पहले सिंगूर और नंदीग्राम में हुआ था। मैं यहां उद्योग या व्यवसाय करने के इच्छुक लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपको भूमि प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। हम सीधे भूमि खरीदेंगे और आपको देंगे।

इस अवसर पर सीएम अधिकारी ने यह भी कहा कि राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त राज्य में स्थिर कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने इस दिशा में कुछ प्रगति की है। हम स्थिर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करके और रिश्वतखोरी एवं जबरन वसूली की पुरानी संस्कृति को पूरी तरह से समाप्त करके उद्योगपतियों के लिए उपयुक्त निवेश वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार की भी आलोचना की, क्योंकि नई भाजपा सरकार को भारी मात्रा में कर्ज विरासत में मिला था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऋण और ब्याज चुकाने में प्रति वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं।

अगर यह पैसा उपलब्ध होता तो इसका उपयोग अधिक विकास कार्यों के लिए किया जा सकता था। यही कारण है कि राज्य को विकास के लिए राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में जितने अधिक उद्योग और कारखाने स्थापित होंगे और जितना अधिक निवेश होगा, उतना ही अधिक राजस्व सरकारी खजाने में आएगा, इसीलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल को एक बार फिर देश के प्रमुख निवेश स्थलों में से एक बनाने के उद्देश्य से काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में अधिक रोजगार सृजन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा, कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल राज्य सरकार की नौकरियों से नहीं हो सकता। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी आवश्यक है। हम राज्य में नए उद्यमों को भी प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराएगी।

मानसून में ग्रामीण भारत को सर्पदंश से बचाने के लिए BSVने अपनी '4A' रणनीति को गति दी

झुंझुनू | बिज़नेस रेमेडीज

मानसून शुरू होते ही भारत के ग्रामीण इलाकों में साँप के काटने की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए मैनकाइंड फार्मा की सहायक कंपनी BSV ने पूरे देश में अपने व्यापक '4A' फ्रेमवर्क को तेज़ी से लागू करना शुरू कर दिया है। BSV ने पिछले दो दशकों से अपनी उच्च गुणवत्ता वाली एंटी-स्नेक वेनम (ASV) दवा के द्वारा इस समस्या से निजात पाने में आम लोगों और स्वास्थ्यकर्मियों की काफी मदद की है।

यह '4A' फ्रेमवर्क चार महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है– जागरूकता, पहुँच , उपलब्धता और त्वरित कार्रवाई। इसका उद्देश्य साँप के काटने की घटनाओं की रोकथाम, समय पर इलाज और मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। BSV का पहला लक्ष्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इसके तहत कंपनी साँप के काटने से जुड़े वर्षों पुराने मिथकों या भ्रांतियों को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित सही प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) और उचित इलाज के बारे में शिक्षित कर रही है।

साँप के काटने की स्थिति में मरीज को जल्द से जल्द नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाना और ग्रामीण तथा सेमी-अर्बन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली एंटी-स्नेक वेनम (ASV) दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहतर इलाज के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है समय पर सही इलाज। यदि सही समय पर उचित उपचार मिल जाए, तो मरीज के मौत होने के रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही लकवा (पैरालिसिस), खून न जमने, अचानक किडनी फेल होने और कई अंगों के एक साथ काम करना बंद कर देने (मल्टी-ऑर्गन फेल्योर) जैसी गंभीर स्थिति में भी बचाव संभव है।

सिवानी शर्मा डेका, COO-India Business, BSV, ने कहा कि एंटी-स्नेक वेनम के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी होने के नाते BSV पिछले दो दशकों से साँप के काटने के इलाज के लिए वैज्ञानिक रूप से उन्नत, उच्च गुणवत्ता वाली और प्रभावी दवाएँ उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साँप के काटने को अधिसूचित बीमारी घोषित करना एक ऐतिहासिक कदम है। इससे मामलों का बेहतर रिकॉर्ड तैयार होगा, एंटी-स्नेक वेनम की आपूर्ति अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी और पूरे देश में एक मजबूत निगरानी प्रणाली विकसित होगी। हालांकि, वर्ष 2030 तक साँप के काटने से होने वाली मौतों को आधा करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आम लोगों में व्यापक जागरूकता फैलाना, हर व्यक्ति तक समय पर इलाज की पहुँच सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण देना और लोगों को सही प्राथमिक उपचार (फस्ट एड) की जानकारी देकर इलाज में होने वाली देरी को रोकना आवश्यक है। एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में BSV लोगों में जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्यकर्मियों को निरंतर चिकित्सा प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सरकार द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस विषय पर बात करते हुए डॉ. आर. के. सुमन, एम.डी. (मेडिसिन), सुमन हॉस्पिटल, झुंझुनू ने कहा, कि भारत में साँप के काटने की घटनाएँ आज भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, देश में हर वर्ष लगभग 58,000 लोगों की मौत साँप के काटने से होती है, जो दुनिया में होने वाली ऐसी कुल मौतों का लगभग आधा है।

साँप के काटने के बाद इलाज में होने वाली हर मिनट की देरी मरीज के बचने की संभावना को काफी कम कर देती है। इसलिए घटना की सही तरीके से पहचान और जल्द से जल्द इलाज तक पहुँच बेहद आवश्यक है। यदि हम लोगों को जागरूक कर साँप के काटने से जुड़े मिथकों को दूर करें और उचित उपचार को अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुँचाने की व्यवस्था मजबूत करें, तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सकता है और हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है।

अजरबैजान में भारतीय समुदाय से मिले राजदूत अभय कुमार, सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने पर जोर

बाकू | बिज़नेस रेमेडीज

अजरबैजान में भारत के राजदूत अभय कुमार ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की और समुदाय से जुड़ी आने वाली गतिविधियों पर चर्चा की। बाकू मलयाली एसोसिएशन (बीएमए) की कार्यकारी समिति के सदस्य प्रवीणकुमार रामचंद्रन नायर और अनस मीरासाहिब ने राजदूत अभय कुमार से मुलाकात की। उन्होंने एसोसिएशन की आने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, जिसमें एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन शामिल है।

राजदूत अभय कुमार ने सुझाव दिया कि बीएमए टूर्नामेंट में अजरबैजान के खिलाड़ियों की ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा दे, ताकि वहां क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि खेल भारत और अजरबैजान के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का एक अच्छा माध्यम हैं। अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास ने 'एक्स' पर बताया कि बातचीत के दौरान बीएमए के आने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई, जिसमें ओणम उत्सव भी शामिल है। राजदूत ने एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यकम दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और एक-दूसरे को बेहतर समझने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय एसोसिएशन ऑफ अजरबैजान के अध्यक्ष प्रशांत मिश्रा ने भी राजदूत अभय कुमार से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन की आगामी गतिविधियों और भारत-अजरबैजान के सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर चर्चा हुई।

राजदूत ने भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआइयू-आईएनडी) के निदेशक अमित मोहन गोविल से भी मुलाकात की, जो एगमोंट ग्रुप की पूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए बाकू में हैं। राजदूत ने एफआइयू-आईएनडी को बाकू में आयोजित प्रतिष्ठित बेस्ट एगमोंट केस अवॉर्ड 2026 में रनर-अप स्थान हासिल करने पर बधाई दी। इससे पहले राजदूत अभय कुमार ने अजरबैजान के प्राचीन गांव खिनालिग का दौरा किया। यह देश के सबसे पुराने पहाड़ी गांवों में से एक है। उन्हें गांव की अनोखी भाषा, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और खास पत्थर की वास्तुकला के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने खिनालिग के हिस्टोरिकल और एथनोग्राफिक म्यूजियम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने दुर्लभ पुरातात्विक खोजों, पुराने हस्तलिखित दस्तावेजों और पारंपरिक वस्तुओं को देखा, जो गांव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। उन्होंने रेड विलेज का भी दौरा किया, जहां माउंटेन यहूदी समुदाय रहता है। इस समुदाय ने सदियों से अपनी अलग भाषा, परंपराओं और विरासत को संभालकर रखा है। राजदूत ने वहां के ऐतिहासिक यहूदी धर्मस्थल और माउंटेन ज्यूइश म्यूजियम का दौरा किया, जहां उन्होंने संग्रहालय के निदेशक इगोर शाउलोव से मुलाकात की।

आइवरी कोस्ट के साथ भारत बढ़ाएगा डिजिटल और कृषि सहयोग

यामूसोक्रो | एजेंसी

विदेश मंत्रालय में केंद्रीय और पश्चिम अफ्रीका के अतिरिक्त सचिव सेवला नाइक मुडे ने आबिदजान में आइवरी कोस्ट के डिजिटल ट्रांजिशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मंत्री जिब्रिल औटारा से मुलाकात की। आइवरी कोस्ट में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि कोटे डी आइवर की राष्ट्रीय विकास योजना 2026-2030 से जुड़े कंसल्टेटिव ग्रुप की बैठकों के दौरान मुडे ने मंत्री जिब्रिल औटारा से मुलाकात की। इस दौरान भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), जैसे यूपीआई और आधार, पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी बात हुई।

भारत की डिजिटल प्रगति की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि वह भारत के सफल डिजिटल सिस्टम से सीखना चाहते हैं। आइवरी कोस्ट में इसी तरह के डिजिटल समाधान अपनाने और लागू करने की संभावनाओं पर काम किया जा सकता है। मुडे ने ब्रूनो मैबाग्ने कोने से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खेती में मशीनों के इस्तेमाल, लोगों को प्रशिक्षण देने, बेहतर बीज उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारतीय दूतावास ने बताया कि 9 जुलाई को आबिदजान में मुडे ने आइवरी कोस्ट के कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य उत्पादन मंत्री ब्रूनो नाबाग्ने कोने से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य विषय खेती को आधुनिक बनाने, क्षमता निर्माण, अच्छी गुणवत्ता के बीज और एग्रो-प्रोसेसिंग में सहयोग बढ़ाना रहा। मुडे ने मंत्री को बताया कि भारतीय कंपनियां आइवरी कोस्ट के एग्रो-प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश कर रही हैं। खास तौर पर काजू, रबर, चावल और दूसरे कृषि उद्योगों में उनका निवेश है। मंत्री ने इस सहयोग को आगे बढ़ाने का स्वागत किया। उन्होंने कृषि मशीनों की सप्लाई, ट्रैक्टर असेंबली जैसी परियोजनाओं में भी रुचि दिखाई और भारतीय कंपनियों को प्रस्ताव पेश करने का निमंत्रण दिया। इसके अलावा मुडे ने ट्रेड, इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट मिनिस्टर इब्राहिम कलील कोनाटे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत और आइवरी कोस्ट के बीच व्यापार और निवेश को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारतीय दूतावास ने बताया कि कोटे डी आइवर की राष्ट्रीय विकास योजना (2026-2030) के लिए वित्त जुटाने से जुड़ी बैठकों के दौरान 9 जुलाई को आबिदजान में मुडे ने इब्राहिम कलील कोनाटे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर बातचीत हुई। मुडे ने यापी कोफी इवारिस्टे, जो आइवरी कोस्ट के विदेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के महासचिव हैं, उनसे भी मुलाकात की। दोनों ने भारत और आइवरी कोस्ट के पुराने और मजबूत रिश्तों को और आगे बढ़ाने के लिए राजनयिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

क्यूबाई समाज के डिजिटल बदलाव प्रोजेक्ट की शुरुआत

बीजिंग | एजेंसी

क्यूबा की राजधानी हवाना में 9 जुलाई को चीनी सरकार और संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के बीच पहली त्रिपक्षीय सहयोग पहल 'क्यूबाई समाज का डिजिटल बदलाव' प्रोजेक्ट का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। यह प्रोजेक्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड साउथ-साउथ कोऑपरेशन फंड की मदद से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्यूबा के दूरसंचार और डिजिटल सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और मजबूत बनाना है, ताकि लोगों को डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।

क्यूबा की संचार मंत्री मायरा अरेविच ने कहा कि यह प्रोजेक्ट देश के डिजिटल बदलाव को गति देगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। क्यूबा में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के उप-आवासीय प्रतिनिधि गेब्रियल बोटिनो ने कहा कि यूएनडीपी इस प्रोजेक्ट को सुचारू और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए हर स्तर पर सहयोग देगा।

इसमें परियोजना का क्रियान्वयन, खरीद प्रक्रिया और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। क्यूबा में चीन के राजदूत ह्वा शिन ने कहा कि 'क्यूबाई समाज का डिजिटल बदलाव' क्यूबा में चीनी सरकार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की पहली त्रिपक्षीय सहयोग परियोजना है। उनके अनुसार, यह चीन और क्यूबा के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम है और बहुपक्षवाद के प्रति चीन की प्रतिबद्धता का भी उदाहरण है।

शोध रिपोर्ट : चीन का विद्युत तकनीकी नवाचार विश्व में प्रथम स्थान पर

बीजिंग | एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच के वैश्विक ऊर्जा इंटरनेट विषयगत कार्यक्रम 10 जुलाई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में जारी 'वैश्विक विद्युत विकास सूचकांक (2026)' शोध रिपोर्ट के अनुसार, चीन की विद्युत विकास समग्र रैंकिंग विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है, जिसमें विद्युत तकनीकी नवाचार विश्व में प्रथम स्थान पर है। रिपोर्ट में आपूर्ति सुरक्षा, उपभोग सेवा, हरित निम्न-कार्बन, और तकनीकी नवाचार समेत चार आयामों के आधार पर दुनिया के 100 देशों की विद्युत विकास स्तर का मूल्यांकन किया गया। समग्र विकास स्तर में शीर्ष पांच देश क्रमशः फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, चीन और नॉर्वे रहे। चीन का विद्युत तकनीकी नवाचार विश्व में प्रथम, स्वच्छ ऊर्जा संस्थापित क्षमता विश्व में प्रथम, तथा विद्युत डिजिटल-बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग विश्व में अग्रणी रहा।

रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में विश्व भर में नवीन ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 3.95 अरब किलोवाट से अधिक हो गई, जो विश्व भर में विद्युत संस्थापित क्षमता का लगभग 40 प्रतिशत है, और वैश्विक विद्युत क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल ट्विन, आभासी विद्युत संयंत्र जैसी प्रौद्योगिकियां अब प्रदर्शन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग की ओर बढ़ रही हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन वैश्विक ऊर्जा इंटरनेट विकास एवं सहयोग संगठन, संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधिमंडल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र एशिया-प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी), तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अध्यक्ष लॉक थापा ने अपने संबोधन में सुझाव दिया कि वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों में हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए, प्रौद्योगिकी के सार्वभौमिक साझाकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, निष्पक्षता-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, तथा नवाचार के माध्यम से एक लचीला और समावेशी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन पथ तैयार किया जाना चाहिए।

नेपाल-भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क लॉन्च

काठमांडू | एजेंसी

दो दर्जन नेपाली स्टार्टअप उद्यमियों को पिछले साल दिसंबर से इस साल जनवरी तक भारत के चेन्नई में आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन में आठ हफ्ते के प्रोग्राम के दौरान मेंटरशिप और मार्केट एक्सपोजर मिला। भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत-नेपाल स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क (आईएन-एसपीएएन) के तहत काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा एक व्यापक प्रक्रिया के जरिए चुने गए 24 उद्यमियों ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया, भारतीय स्टार्टअप्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और सोलर फोटोवोल्टिक्स में स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरे किए और भारतीय स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप की। इस प्रोग्राम के अच्छे नतीजे भी मिले, जिसमें नौ नेपाली स्टार्टअप्स को आईआईटी मद्रास इनक्यूबेशन सेल से इनक्यूबेशन और निवेश ऑफर मिले, जो भारत के लीडिंग डीप-टेक इनक्यूबेटर्स में से एक है।

प्रतिभागी भारत-नेपाल स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क (आईएन-एसपीएएन) का हिस्सा थे, जो काठमांडू में भारतीय दूतावास और आईआईटीएम प्रवर्तक की एक संयुक्त पहल है, जिसका मकसद उभरते हुए नेपाली उद्यमियों को भारत के इनोवेशन, तकनीक और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ना है। भारत में लगभग दो महीने के प्रोग्राम से लौटने के बाद, प्रतिभागियों ने आईएन-एसपीएएन से आए मोमेंटम को नेपाल में भी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने एक स्थायी संस्थान, आईएन-एसपीएएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, जिसका मकसद नेपाल में एक सेल्फ-सस्टेनिंग द्विपक्षीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है, जहां दोनों देशों के संस्थापक, शोधकर्ता और संस्थान मिलकर काम कर सकें। इसका मकसद उद्यमिता को मजबूत करने के एक जैसे दृष्टिकोण के साथ अकादमी, उद्योग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच स्ट्रक्चर्ड इनक्यूबेशन, क्रॉस-बॉर्डर कोलेबोरेशन और साझेदारी को बढ़ावा देना है। नए बने संस्थान ने 2026-2029 टर्म के लिए फॉर्मल तौर पर नौ मेंबर का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया है। बोर्ड को प्रेसिडेंट असीम श्रेष्ठ हेड कर रहे हैं, जिसमें प्रबीन भट्टाराई वाइस-प्रेसिडेंट, श्रीयांच श्रेष्ठ जनरल सेक्रेटरी, ऋतिक बाबू श्रेष्ठ जॉइंट सेक्रेटरी और प्रदीप गिरी ट्रेजरर हैं। ऑर्गनाइजेशन की तरफ से जारी एक प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक, मोहन तमांग, विष्णु कुमार अग्रवाल, निकेश सिंह और सुनील के.सी. को एग्जीक्यूटिव मेंबर चुना गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनने के बाद, ऑर्गनाइजेशन ने तीन साल का रोडमैप जारी किया, जिसका मकसद भारत के साथ क्रॉस-बॉर्डर कोलेबोरेशन के ज़रिए नेपाल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है। आईएन-एसपीएएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने 2026-2029 के समय के लिए पांच-पॉइंट रोडमैप को मंजूरी दी है। इस प्लान के तहत, काठमांडू में एक फ्लैगशिप इनक्यूबेशन सेंटर बनाना है, जो हर साल 25 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा। हर साल लगभग 500 उद्यमियों के लिए फाउंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा। नेपाल और भारत के इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हर महीने टाउन हॉल इंटरेक्शन आयोजित करेगा।

बीमा/ बैंकिंग/ ज्वैलरी

Emerging Entrepreneur

अजय जैन और अमित श्रीवास्तव ने 9DXR लैब्स को एक इमर्सिव लर्निंग कंपनी कैसे बनाया

जयपुर | बिज़नेस रेमेडीज

2017 में अजय जैन और अमित श्रीवास्तव ने शुरू किया था। इसका मकसद एक आसान लेकिन बड़ा लक्ष्य था कि हर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल साइंस की शिक्षा मिल सके, भले ही उनके स्कूल में पूरी तरह से तैयार लैब हो या न हो। गुरुग्राम, हरियाणा में हेडक्वार्टर वाली इस कंपनी ने महसूस किया कि कई स्कूल इंफ्रास्टक्चर, लागत और सुरक्षा की दिक्क तों की वजह से हैंड्स-ऑन एक्सपेरिमेंट देने में मुश्किल महसूस करते हैं। इन चुनौतियों को रुकावट समझने के बजाय, फाउंडर्स ने एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि ऐसे इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस बनाए जा सकें जो वर्चुअल माहौल में साइंस के पाठों को असलियत में बदल सकें। उनका विज़न पैसिव लर्निंग को एक्टिव पार्टिसिपेशन से बदलना था, ताकि स्टूडेंट सिर्फ पढ़कर ही कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस करके समझ सकें। एक्सआर लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल रियलिटी साइंस लैब्स, इमर्सिव एसटीईएम लर्निंग सॉल्यूशंस, हैंड ट्रैकिंग बेस्ड वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स और करिकुलम अलाइन्ड डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स पर केंद्रित इनोवेटिव एजुकेशन सॉल्यूशंस के पोर्टफोलियो को जन्म दिया। के-12 स्कूलों के लिए डिजाइन किए गए ये ऑफर स्टूडेंट्स को साइंस एक्सपेरिमेंट करने, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करने और सुरक्षित और आकर्षक सेटिंग में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने में इनेबल करते हैं। साथ ही, टीचर्स को लेसन मैनेज करने और स्टूडेंट प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए टूल्स मिलते हैं, जिससे इमर्सिव एजुकेशन रोजमर्रा की क्लासरूम्स के लिए प्रैक्टिकल हो जाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मौजूदा स्कूल करिकुलम के साथ मिलाकर, 9डीएक्सआर लैब्स ने खुद को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी से कहीं ज्यादा के तौर पर स्थापित किया है–यह साइंस एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में पार्टनर बन गया है। शार्क टैंक इंडिया सीज़न 5 में आने के बाद स्टार्टअप को पूरे देश में पहचान मिली, जहाँ अजय जैन ने इन्वेस्टर्स के पैनल के सामने कंपनी का विज़न पेश किया। 4 परसेंट इक्विटी के बदले 1 करोड़ मांगते हुए, फाउंडर्स ने दिखाया कि कैसे इमर्सिव लर्निंग थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल समझ के बीच के गैप को कम कर सकती है। हालाँकि शार्क्स ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल असर की तारीफ़ की, लेकिन स्टार्टअप ने आखिरकार बिना इन्वेस्टमेंट हासिल किए शो छोड़ दिया। फिर भी, पूरे देश में पहचान मिलने से 9DXR लैब्स को एजुकेटर्स, स्कूलों और टेक्नोलॉजी के शौकीनों के ज़्यादा बड़े ऑडियंस से मिलवाया, जिससे यह साबित हुआ कि एक यादगार पिच बिना किसी डील के भी विज़िबिलिटी पैदा कर सकती है।

कई एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के उलट, जो ज़्यादातर रिकॉर्ड किए गए लेक्चर या डिजिटल कंटेंट पर फोकस करती हैं, 9DXR लैब्स ने एक्सपीरिएंशियल लर्निंग के आस-पास अपनी पहचान बनाई है। इसका इमर्सिव प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देता है, जिससे मुश्किल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को देखना और समझना आसान हो जाता है। यह तरीका उन स्कूलों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिनके पास लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक सिलेबस के साथ बने रहते हुए वर्चुअल सेटिंग में सुरक्षित रूप से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कंपनी के इंटरैक्टिव लर्निंग पर ज़ोर देने से उसे भारत के तेज़ी से कॉम्पिटिटिव होते EdTech माहौल में अलग दिखने में मदद मिली है, जहाँ एंगेजमेंट और प्रैक्टिकल समझ डिजिटल कंटेंट तक पहुँच जितनी ही ज़रूरी होती जा रही है।

आज, 9DXR लैब्स एक एक्टिव कंपनी के तौर पर काम कर रही है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है और एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी से चलने वाले इमर्सिव क्लासरूम एक्सपीरियंस को बढ़ावा दे रही है। इसके लगातार ऑपरेशन दिखाते हैं कि बिज़नेस ने शार्क टैंक इंडिया में अपनी मौजूदगी से आगे बढ़कर साइंस एजुकेशन को बदलने का अपना कमिटमेंट बनाए रखा है। हालांकि टेलीविज़न का सफ़र किसी इन्वेस्टमेंट के साथ खत्म नहीं हुआ, लेकिन फाउंडर अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने और देश भर के ज़्यादा स्कूलों तक पहुंचने पर फोकस करते रहे। उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक असली प्रॉब्लम को पहचानना, इनोवेशन को अपनाना और लॉन्ग-टर्म विज़न के लिए कमिटेड रहना एक स्टार्टअप को क्रेडिबिलिटी बनाने और तब भी आगे बढ़ते रहने में मदद कर सकता है, जब तुरंत फंडिंग न मिले।

भारत की ग्रोथ का नया इंजन बना सर्विसेज सेक्टर, 3-5 साल के निवेशकों के लिए क्यों है बड़ा मौका?

जितेंद्र श्रीराम, सीनियर फंड मैनेजर (इक्विटी), बड़ौदा बीएनपी परिबा एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

मुंबई | बिज़नेस रेमेडीज

भारत के ग्रोथ स्टोरी की बात होती है, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नाम आता है। पिछले कुछ साल में सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी योजनाएं काफी चर्चा में रही हैं। लेकिन इस बदलाव के पीछे एक और मजबूत ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। यह ट्रेंड है सर्विसेज सेक्टर की तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी। लंबी अवधि के नजरिए से देखें, तो यह सेक्टर निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक निवेश अवसरों में से एक बन सकता है।

सर्विसेज इकोनॉमी अब भारत का नया ग्रोथ इंजन : पिछले 2 दशक में ग्रॉस वैल्यू ऐडेड (GVA) के लिहाज से भारत की सर्विसेज सेक्टर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों से तेजी से बढ़ा है। भारत ने भारी मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा निर्भर रहने के बजाय सीधे टेक्नोलॉजी और सर्विसेज आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं।

आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। FY26 में भारत के कुल GVA में सर्विसेज सेक्टर की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत और एग्रीकल्चर की 14 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ को मजबूत करने वाले 5 फैक्टर

भारत का सर्विसेज सेक्टर कई ऐसे लॉन्ग टर्म फैक्टर्स की वजह से तेजी से बढ़ रहा है, जो आने वाले सालों में भी इसकी ग्रोथ को सपोर्ट दे सकते हैं।

1. **अर्थव्यवस्था का औपचारिक होना :** देश में बड़ी संख्या में कर्मचारी कैश बेस्ड इन्फॉर्मल इकोनॉमी से निकलकर फॉर्मल सेक्टर में आ रहे हैं। इससे लोगों को रेगुलर सैलरी, बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल और डिजिटल फाइनेंशियल रिकॉर्ड मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के इस औपचारिक होने से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ती है और अलग अलग सर्विसेज कंपनियों के लिए ग्राहकों का दायरा भी बड़ा होता है। इससे कई तरह के सर्विसेज बिजनेस को फायदा मिलता है।

2. **भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन :** अब भारत की करीब 70त्न आबादी इंटरनेट से जुड़ चुकी है, जिससे देश दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इस मजबूत डिजिटल व्यवस्था की वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थकेयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल और ई-कॉमर्स जैसे कई क्षेत्रों में आने वाले साल तक बड़े अवसर बनने की संभावना है।

3. **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर :** यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए नए ग्राहक जोड़ने की लागत काफी कम कर दी है और डिजिटल पेमेंट को बेहद आसान बना दिया है। इससे लोगों ने डिजिटल सर्विसेज को तेजी से अपनाया है, कंपनियों की कामकाज करने की दक्षता बढ़ी है और कई सर्विस इंडस्ट्रीज की प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार हुआ है।

4. **प्रीमियम सर्विसेज की बढ़ती मांग :** जैसे-जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, शहरों में रहने वालों की संख्या बढ़ रही है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे वे बेहतर और प्रीमियम सर्विसेज की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से हॉस्पिटैलिटी से जुड़े कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही हेल्थकेयर, एजुकेशन और अन्य सेवाओं में भी बेहतर और आसानी से उपलब्ध सुविधाओं की मांग लगातार बढ़ रही है।

5. **सरकार का मजबूत पॉलिसी सपोर्ट :** केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत को दुनिया का प्रमुख सर्विसेज हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 2047 तक ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

ट्रांसयूनियन सिबिल और सिडबी द्वारा एमएसएमई पल्स रिपोर्ट जारी

मुंबई | एजेंसी

ट्रांसयूनियन सिबिल और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) द्वारा जारी की गई नवीनतम एमएसएमई पल्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत के वाणिज्यिक ऋण बाजार में कर्ज लेने वालों के ढांचे में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अब व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लोन लेने वाले व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की कुल वाणिज्यिक ऋण बकाया में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हो गई है। कुल बकाया वाणिज्यिक ऋण में से व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत रही, जबकि कंपनियों या संस्थाओं को दिए गए ऋणों की हिस्सेदारी 72 प्रतिशत थी। मार्च 2023 से मार्च 2026 के बीच तीन साल की अवधि के दौरान, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं का बकाया ऋण 1.8 गुना बढ़ा है, जबकि इसी अवधि में संस्थागत उधारकर्ताओं के ऋण में 1.5 गुना की वृद्धि देखी गई है।

ट्रांसयूनियन सिबिल के एमडी और सीईओ भावेश जैन ने कहा कि जैसे-जैसे एमएसएमई का विकास होता है, उनकी ऋण संबंधी जरूरतें भी बदलती हैं, छोटे वर्किंग कैपिटल लोन से लेकर बड़े और सेक्टर-आधारित फंडिंग की आवश्यकताओं तक। बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के लिए वास्तविक अवसर इस बदलाव को और अधिक स्पष्टता से समझने में है।

'उम्मेद भवन' दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक

बिज़नेस रेमेडीज/जोधपुर

उम्मैद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महल है। यह दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। यह ताज होटल का ही एक अंग है। इसका नाम महाराजा उम्मैद सिंह के पौत्र ने दिया था जो वर्तमान में मालिक है। अभी वर्तमान समय में इस पैलेस में 347 कमरे है। इस उम्मैद भवन पैलेस को चित्तर पैलेस के नाम से भी पहले जाना जाता था जब इसका निर्माण कार्य चालू था। यह पैलेस 1943 में बनकर तैयार हुआ था। आजादी के बाद वर्ष 1978 में इसे होटल में बदल दिया गया। हालांकि आज भी इसके एक भाग में पूर्व नरेश का परिवार रहता है। जोधपुर के प्रसिद्ध चित्तर पत्थर से बना होने के कारण स्थानीय लोग इसे चित्तर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। महल को तराशे गए बलुआ पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। मजे की बात यह है कि पत्थरों को बांधने के लिए किसी मसाले का उपयोग नहीं किया गया।

जब आप किसी राजसी किले की ऊंची दीवारों, बुर्ज और उसकी जटिल बनावट से रूबरू होते हैं, उसके झरोखों से बाहर दूर तक झांकते हैं और यह सुनते हैं कि राज्य की आन-बान-शान के लिए यहां के सैनिक दुश्मन सैनिकों से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी देने में जरा भी नहीं हिचके, तो आप निश्चित रूप से अपनी उस विरासत से मुलाकात करते हैं जो इतिहास के पन्नों में आज भी गर्व से जीवित है। इसके अलावा, जब आपको राजा-महाराजाओं के महल में उनके समय के जैसे ठाठ-बाट के साथ लगभग उसी माहौल में रहने का अवसर मिलता है, तो एकबारगी आपको ऐसा लग सकता है जैसे आप खुद वहां के महाराजा या फिर राजपरिवार के सदस्य हों। यह एहसास आपके लिए ताउम्र न भूलने वाला हो सकता है। और अगर मन में कहीं उनकी शानो-शौकत को महसूस करने की इच्छा है, तो महलों में रात गुजारिए। भले ही अब राजा-महाराजा और उनकी शानो-शौकत बरकरार न हो, लेकिन उनके रुतबे और शाही ठाट-बाट का अनुभव आज के समय में आप भी किलों और महलों में जाकर काफी हद तक हासिल कर सकते हैं। दरअसल, राजसी गौरव के प्रतीक कई किले और महल आज लक्जरी होटलों में तब्दील हो चुके हैं, जहां आधुनिक युग की तमाम सुख-सुविधाओं के साथ हेरिटेज फील को भी काफी हद तक संजोया गया है। पर्यटन के लिहाज से इन किलों और महलों की सैर काफी रोमांचकारी साबित हो सकती है। यहां पर रुकना एक राजसी एहसास और इतिहास के उन पलों में लौटने जैसा है।

वैभव का गवाह उम्मेद भवन

शाही समृद्ध विरासत और संस्कृति के धनी राजस्थान में राजसी महलों की शान अद्भुत है। जोधपुर का शाही महल उम्मेद भवन पैलेस हर राजसी परंपरा से आपका परिचय कराता है। इसके मालिक हैं महाराजा गज सिंह। उनके पिता महाराजा उम्मेद सिंह ने इसे बनवाया था। इसके संग्रहालय में राजसी हवाई जहाज के मॉडलों, हथियारों, प्राचीन वस्तुओं, घड़ियों, बॉब घड़ियों, बर्तनों, कटलरी, तस्वीरों और शिकार की ट्रॉफियां तक संजोयी गई हैं। आज यह महल बड़े बिजनेस घरानों की शाही शादियों और बॉलीवुड फिल्मों के लिए रॉयल डेस्टिनेशन है। वर्तमान में उम्मैद भवन पैलेस का मालिक गज सिंह है। इस पैलेस के तीन भाग है , एक लग्ज़री ताज होटल जो (1972) से है ,एक शाही परिवार के लिए तथा एक संग्रहालय है। संग्रहालय के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 तक। यहाँ एक दीर्घा भी है जहाँ पर कई चीजें देखने को मिलती है।

एअर इंडिया दुनिया की टॉप 5 समय की सबसे पाबंद ग्लोबल एयरलाइंस में शामिल

जून 2026 में सिरियम द्वारा जारी ऑन-टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में चौथे स्थान पर

गुरूग्राम | बिज़नेस रेमेडीज

एविएशन एनालिटिक्स फर्म सिरियम ने जून 2026 में एअर इंडिया को दुनिया की चौथी समय की सबसे पाबंद एयरलाइन का दर्जा दिया है। यह भरोसेमंद संचालन और शेड्यूल के अनुपालन पर एयरलाईन के लगातार फोकस को दर्शाता है।

सिरियम द्वारा जून 2026 में जारी ऑन-टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार, इस माह के दौरान एअर इंडिया 15,135 उड़ानों को ट्रैक किया गया, जिनमें से 86.85 उड़ानें समय पर पहुंची। इसी तरह 86.23 फीसदी उड़ानें समय पर रवाना हुई और एयरलाईन ने 99.7 फीसदी का कंप्लीशन फैक्टर भी दर्ज किया, यानि लगभग सभी शेड्यूल्ड उड़ानें योजना के अनुसार संचालित हुई। यह रैंकिंग संचालन की मजबूती, नेटवर्क की बेहतर प्लानिंग तथा डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल संचालन में एअर इंडिया द्वारा लगातार किए जा रहे निवेश को दिखाती है।

भारत के दो सबसे बड़े एयरपोर्ट्स - दिल्ली और मुंबई - के जरिए बड़ी संख्या में डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल कनेक्शन का संचालन करने वाली हब-एंड-स्पोक नेटवर्क एयरलाइन के रूप में एअर इंडिया संचालन की मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन व्यस्त एयरपोर्ट्स पर भीड़ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पाबंदियों के कारण एयरलाइन के संचालन पर असर पड़ सकता है, जो अक्सर पूरे नेटवर्क को प्रभावित करता है।

समय के साथ, एअर इंडिया ने अपने शेड्यूल की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने और मेहमानों को यात्रा का उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें उड़ान उड़ान को समय पर रवाना करना, विमान के टर्नअराउंड प्रोसेस को आसान बनाना, रियल-टाइम नेटवर्क मॉनिटरिंग को बेहतर बनाना और एयरलाइन में तेजी से ऑपरेशनल फैसले लेने की क्षमता बढ़ाना शामिल है।

एयरलाइन ने मजबूत आकस्मिक योजना, बेहतर क्रॉस-फंक्शनल तालमेल और ऑपरेशनल प्रत्यास्थता के जरिए संचालन को सक्षम बनाने पर भी ध्यान दिया है। जो मौसम की परिस्थितियों, एयरस्पेस की पाबंदियों, एयरपोर्ट पर भीड़ या तकनीकी दिक्कतों जैसी अचानक आने वाली रुकावटों से निपटने के लिए जरूरी है। इन कोशिशों से रुकावटों का प्रभाव कम करने, नेटवर्क को स्थिर रखने और मेहमानों के अपनी मंजिल तक ज़्यादा भरोसे के साथ पहुँचने में मदद मिलती है। वर्तमान में चल रहे बदलाव के बड़े प्रयासों के तहत एअर इंडिया अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बना रही है। इन प्रयासों में फ्लीट का आधुनिकीकरण, मेहमानों के अनुभव को बेहतर बनाना, डिजिटल इनोवेशन और अपने बढ़ते हब-एंड-स्पोक नेटवर्क के जरिए ग्लोबल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना शामिल है।

फ्लीट को आधुनिक बनाने की कोशिशें : अपने बदलाव के तहत एअर इंडिया दुनिया के सबसे बड़े फ्लीट के नवीनीकरण पर काम कर रही है। एअर इंडिया 600 नए एयरबस और बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया है और साथ ही अपने मौजूदा फ्लीट को भी आधुनिक बना रही है। एयरलाइन ने पिछले छह महीनों में तीन नए बोइंग 787-9 विमान शामिल किए हैं, तथा 2026 में बोइंग 787-9 और एयरबस ए350-1000 विमानों के फ्लीट में शामिल होने की उम्मीद है।

इसके साथ एअर इंडिया अपने पुराने वाइडबॉडी फ्लीट को अपग्रेड (रीट्रोफिट) करने का काम भी कर रही है। इनके 26 पुराने बोइंग 787-8 विमानों में से दो, जिनके इंटीरियर को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है, पहले ही सेवा में लौट चुके हैं, जबकि तीन अन्य विमानों को अभी अमेरिका में अपग्रेड किया जा रहा है। 2026 के अंत तक, एअर इंडिया के वाइडबॉडी फ्लीट में 50 फीसदी से अधिक विमानों में नए या अपग्रेडेड इंटीरियर होंगे, जिससे एयरलाइन के लंबी दूरी के नेटवर्क पर मेहमानों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

पीएम लक्सन ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए आधारित नई डील का ऐलान किया

ऑकलैंड | एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड समेत तीन देशों का छह दिवसीय दौरा खत्म कर चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे के खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने जानकारी दी है कि न्यूजीलैंड और भारत एक नए समझौते पर सहमत हुए हैं जो हमारे मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर आधारित है।

पीएम लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'न्यूजीलैंड और भारत एक नई डील पर सहमत हुए हैं जो हमारे मुक्त व्यापार समझौते पर आधारित है। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, हमने अपने संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है, जिसमें 2030 तक हमारे देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने की योजना है। इसका मतलब है कि कीवी समुदाय में ज्यादा पैसा वापस आएगा, नौकरियां पैदा होंगी और घर पर सैलरी बढ़ेगी।'

एट्रियल फिब्रिलेशन में एंटीकोआगुलेशन स्टीवर्डशिप को बढ़ावा देने और स्ट्रोक की रोकथाम मजबूत करने के लिए फाइज़र ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जयपुर के साथ साझेदारी की

जयपुर | बिज़नेस रेमेडीज

फाइज़र ने 'एसीई-केयर नेटवर्क' पहल के तहत महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एमजीएमसीएच), जयपुर के साथ मिलकर एक वैज्ञानिक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य अस्पताल- आधारित एंटीकोआगुलेशन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम के विकास को समर्थन देना है। यह कार्यक्रम एट्रियल फिब्रिलेशन (एएफ) के बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित है। एएफ एक सामान्य हृदय-लय विकार है, जिसमें स्ट्रोक का जोखिम काफी बढ़ जाता है। इस पहल के जरिए साक्ष्य-आधारित उपचार, एकरूप प्रोटोकॉल और विभिन्न विशेषज्ञताओं के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा दिया जा रहा है।

फाइज़र में मेडिकल अफेयर्स के प्रमुख, डॉ. पंकज गुप्ता ने कहा किएट्रियल फिब्रिलेशन के मरीजों के बेहतर परिणाम के लिए विभिन्न विशेषज्ञताओं के बीच मजबूत समन्वय जरूरी है। 'एसीई-केयर नेटवर्क' के तहत इस साझेदारी के माध्यम से हम चिकित्सकों को नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और उपचार में एकरूपता को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे

स्ट्रोक का जोखिम कम किया जा सके। एमजीयूएमएसटी के प्रो-वाइस चांसलर और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रोफेसर, डॉ. वी.के. कपूर ने कहा, कि एमजीएमसीएच 'एसीई-केयर नेटवर्क' पहल के माध्यम से फाइज़र के साथ साझेदारी कर एंटीकोआगुलेशन स्टीवर्डशिप को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न विशेषज्ञताओं के बीच समन्वित दृष्टिकोण जरूरी है, ताकि जोखिम कम करते हुए मरीजों को सही समय पर उपयुक्त उपचार मिल सके। ऐसी पहलें जागरूकता बढ़ाने, सर्वोत्तम प्रथाओं को मानकीकृत करने और मरीजों की सुरक्षा व उपचार परिणामों में सुधार में मदद करती हैं। कार्यक्रम में 100 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों ने भाग लिया। इसमें विशेषज्ञों के नेतृत्व में वैज्ञानिक सत्र, केस चर्चा और तृतीयक देखभाल में एंटीकोआगुलेशन से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों पर बहु-विषयक विचार-विमर्श शामिल रहा। चर्चाओं में एएफ में स्ट्रोक की रोकथाम, पोस्ट-एसीएस/पीसीआई एंटीकोआगुलेशन से जुड़े निर्णय, स्ट्रोक मरीजों में छूटे हुए एएफ की पहचान, तीव्र वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, उच्च जोखिम वाले मरीजों की प्रोफाइल, तथा एंटीकोआगुलेशन थेरेपी की शुरुआत, अस्थायी रोक, पुनः शुरुआत और निगरानी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में एंटीकोआगुलेशन से जुड़े फैसले किसी एक चिकित्सक तक सीमित न रहकर अस्पताल-स्तर की स्टीवर्डशिप व्यवस्था के तहत लिए जाएं। यह व्यवस्था साझा मानकों, स्पष्ट जवाबदेही, व्यवस्थित संचार और मरीज-केंद्रित फॉलो-अप पर आधारित होनी चाहिए। तृतीयक देखभाल अस्पतालों में, जहां मरीज इमरजेंसी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, आईसीयू, मेडिसिन और डिस्चार्ज जैसी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, हर स्थानांतरण उपचार की निरंतरता और मरीज की सुरक्षा बेहतर करने का अवसर होता है। भारत में एट्रियल फिब्रिलेशन के लगभग 79 लाख मामले अनुमानित हैं और यह संख्या दुनिया में दूसरी सबसे अधिक है। एएफ से पीड़ित लोगों में सामान्य हृदय-लय वाले लोगों की तुलना में स्ट्रोक का जोखिम तीन से पांच गुना अधिक होता है। ऐसे में समय पर पहचान, जोखिम-आधारित उपचार और नियमित पुनर्मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है। यह पहल अस्पताल के विभिन्न विभागों के बीच एंटीकोआगुलेशन प्रबंधन को लेकर एक समान समझ विकसित करने पर केंद्रित है। 'एसीई-केयर' का उद्देश्य सुरक्षित निर्णय-प्रक्रिया को बढ़ावा देना, उपचार में अनावश्यक भिन्नताओं को कम करना और निदान से लेकर डिस्चार्ज व फॉलो-अप तक देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम दिशानिर्देशों को व्यावहारिक,अस्पताल-उपयोगी प्रक्रियाओं में बदलने में मदद करता है। इसके प्रमुख तत्व हैं- जोखिम का आकलन और उपयुक्त उपचार निर्णय, मानकीकृत एंटीकोआगुलेशन उपचार मार्ग, बहु-विशेषज्ञता समन्वय, देखभाल के विभिन्न चरणों में सुरक्षा सुनिश्चित करना, मरीज-केंद्रित परामर्श और दवा अनुपालन में सहयोग, मूल्यांकन और निरंतर सुधार।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'द हार्ट ऑफ ए जैन' की शुरुआत

जयपुर | बिज़नेस रेमेडीज

जैन धर्म को 'सभी धर्मों की जननी' बताते हुए, हार्टफुलनेस के मार्गदर्शक और रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष पूज्य दाजी ने जैन समुदाय से अपनी प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को केवल दर्शन और अनुष्ठानों तक सीमित न रखकर उसे जीवंत अनुभव, नैतिक आचरण और पारिस्थितिक जिम्मेदारी में बदलने का आग्रह किया। जैन धर्म को भगवान ऋषभदेव की सभ्यतागत विरासत से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'द हार्ट ऑफ ए जैन' की शुरुआत हैदराबाद के हार्टफुलनेस संस्थान के मुख्यालय, कान्हा शांति वनम में हुई।

कार्यक्रम के विशिष्ट मुख्य अतिथियों में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तन्य काश्यप और जैन धर्म के विद्वान पद्मश्री कुमारपाल देसाई शामिल थे। भारत और विदेशों से 100 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं, जिनमें संयोजक के रूप में कार्यरत जैन नेता जैसे कुशल भंसाली, रमेश जैन, कुशल कुमार कांकरिया और डॉ. शर्मिला ओसवाल शामिल हैं।

यह सम्मेलन जैन ज्ञान की समकालीन प्रासंगिकता तलाशने के लिए 100 से अधिक जैन विद्वानों, दार्शनिकों, आध्यात्मिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और समुदाय के प्रतिनिधियों को एक साथ मंच पर लाया। सम्मेलन का उद्देश्य आधुनिक युग में चेतना, नैतिकता, स्थिरता और मानव विकास को संबोधित करने वाले एक परिवर्तनकारी संवाद के केंद्र में समकालीन जैन धर्म को भगवान ऋषभदेव की सभ्यतागत विरासत से फिर से जोड़ना था और हरी यूनिवर्सिटी में प्रस्तावित 'भगवान ऋषभदेव दर्शन पीठ' के लिए एक रूपरेखा विकसित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत हार्टफुलनेस के मार्गदर्शक व रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष पूज्य दाजी के नेतृत्व में एक निर्देशित हार्टफुलनेस ध्यान सत्र के साथ हुई। अभिनेता विद्युत जामवाल और पूज्य दाजी के बीच चर्चा हुई, जिसमें दाजी ने आज के युवाओं और उनकी तार्किकता, 'प्राणाहुति' के माध्यम से ध्यान की उत्पत्ति और उद्देश्य, तीर्थंकरों के योगदान और आत्म-निरीक्षण के बिंदुओं पर सवालों के जवाब दिए। दाजी ने कहा, कि जब किसी को अनुभव प्राप्त हो जाता है, तो उसे विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। अनुभव के साथ विश्वास विलीन हो जाता है। दाजी ने कहा कि भारत को केवल एक दार्शनिक पुनरुत्थान से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए लोगों के सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके में गहरे रूपांतरण की जरूरत है। उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों को रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए व्यावहारिक तरीकों के रूप में हार्टफुलनेस ध्यान, आंतरिक सफाई और प्राणाहुति को प्रस्तुत किया।

एसएचएम शिपकेयर 'नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पोर्ट्स एंड शिपिंग, 2026' से सम्मानित

मुंबई | बिज़नेस रेमेडीज

जहाज बनाने, जहाज के मैनेजमेंट और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों में से एक एसएचएम शिपकेयर प्राइवेट लिमिटेड ('एसएचएम शिपकेयर') को 'आउटस्टैंडिंग इंडस्ट्री अचीवमेंट' (उद्योग में बेहतरीन उपलब्धि) कैटेगरी में 'नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पोर्ट्स एंड शिपिंग, 2026' से सम्मानित किया गया। पोर्ट और शिपिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए दिए जाने वाले 'नेशनल अवार्ड्स' इस इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक हैं। ये पुरस्कार भारत के मैरीटाइम और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में शानदार योगदान देने वाले संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं।

एसएचएम शिपकेयर के मरीन और फायर सेफ्टी सीईओ मोहम्मद हाजी ने कहा कि मरीन सेफ्टी सिस्टम बहुत जरूरी होते हैं और इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना समुद्री इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड-क्लास, आत्मनिर्भर समाधान बनाने के हमारे संकल्प को और मज़बूत करता है। एसएचएम शिपकेयर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सैफुद्दीन हाजी ने कहा कि यह सम्मान भारत की पहली स्वदेशी लाइफबोट बनाने में की गई सालों की इंजीनियरिंग कोशिशों का सबूत है।

एमआईटी-डब्ल्यूपीयू ने की 'हाफीज कॉन्ट्रैक्टर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर' की शुरुआत

पुणे | बिज़नेस रेमेडीज

भारत में वास्तुकला (आर्किटेक्चरल) शिक्षा को एक नई दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, डॉ. विश्वनाथ कराड एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने 'हाफीज कॉन्ट्रैक्टर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर' की स्थापना की घोषणा की है। इस प्रतिष्ठित नए स्कूल की स्थापना भारत के सबसे प्रसिद्ध वास्तुकारों में से एक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित, आर्किटेक्ट हाफीज कॉन्ट्रैक्टर के सम्मान में की गई है। देश के सबसे प्रभावशाली वास्तुकारों में से एक माने जाने वाले हाफीज कॉन्ट्रैक्टर ने पिछले चार दशकों से अधिक के समय में कई ऐतिहासिक आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और टाउनशिप परियोजनाओं के माध्यम से भारत के शहरी परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। अपनी समकालीन डिजाइन शैली, बड़े पैमाने पर नगर नियोजन (प्लानिंग) विशेषज्ञता और भारतीय वास्तुकला में अद्वितीय योगदान के लिए पहचाने जाने वाले हाफीज कॉन्ट्रैक्टर का नाम उत्कृष्टता, नवाचार और दूरदर्शी सोच का पर्याय बन चुका है।

इसी शानदार विरासत से प्रेरणा लेते हुए, यह स्कूल छात्रों को उद्योग के अनुकूल और भविष्य पर केंद्रित एक बेहतरीन शैक्षणिक माहौल प्रदान करेगा। इसमें वास्तुकला के उत्कृष्ट डिजाइन के साथ-साथ स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी), तकनीकी नवाचार और व्यावहारिक अनुभव का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा। इस स्कूल का प्रमुख पाठ्यक्रम, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर , पांच साल का एक व्यावसायिक डिग्री प्रोग्राम है। यह पाठ्यक्रम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिल्कुल अनुरूप तैयार किया गया है। स्टूडियो-आधारित इस पाठ्यक्रम में आर्किटेक्चरल डिजाइन, बिल्डिंग साइंसेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, अनुसंधान, व्यावसायिक अभ्यास और स्थिरता को पूरी तरह एकीकृत किया गया है। यहां छात्रों को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का लाभ मिलेगा, जिसमें उन्नत डिजाइन स्टूडियो, क्लाइमेटोलॉजी और सर्वेइंग लैबोरेट्रीज, मटीरियल म्यूजियम, डिजिटल डिजाइन सुविधाएं और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, कंप्यूटेशनल डिजाइन व इमर्सिव टेक्नोलॉजी का व्यावहारिक अनुभव शामिल है। इस अवसर पर स्कूल ऑफ डिजाइन के डीन, डॉ. सुमन देवदुला ने कहा, कि हाफीज कॉन्ट्रैक्टर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की स्थापना एमआईटी-डब्ल्यूपीयू के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। भारतीय वास्तुकला में हाफीज कॉन्ट्रैक्टर के असाधारण योगदान ने वास्तुकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनके नाम को हमारे स्कूल से जोड़कर, हम एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहते हैं जहां नवाचार, रचनात्मकता, स्थिरता व व्यावहारिक शिक्षा का संगम हो।

एसर ने 64 मेगापिक्सल कैमरे और डुअल डिस्प्ले वाला नया स्मार्टफोन पेश किया

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

लैपटॉप बनाने वाली कंपनी एसर ने अपना नया स्मार्टफोन एसर सोस्पिरो ए15 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 64 मेगापिक्सल कैमरे, एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले, यूनिसॉक चिपसेट, 6 जीबी रैम, 128 जीबी स्टोरेज और 5000 एमएएच बैटरी के साथ बाजार में उतारा है। इसके साथ 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। एसर ने एसर सोस्पिरो ए15 को अमेरिकी बाजार में लॉन्च किया है। कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। स्मार्टफोन को आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया है। इसे ऑरेंज और ब्लू रंग विकल्पों में पेश किया गया है। एसर सोस्पिरो ए15 में 6.67 इंच का एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और वॉटरड्रॉप नॉच डिजाइन मिलता है। इस फोन की सबसे खास बात इसका रियर डिस्प्ले है। पीछे की तरफ 1.88 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है, जिसका उपयोग नोटिफिकेशन देखने, संगीत नियंत्रित करने और मुख्य कैमरे से सेल्फी लेने के लिए व्यूफाइंडर के रूप में किया जा सकता है। प्रोसेसिंग के लिए इसमें यूनिसॉक टी615 चिपसेट दिया गया है। हालांकि, इसमें 5जी कनेक्टिविटी नहीं होने से कुछ यूजर्स निराश हो सकते हैं। फोन में 6 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह 14 जीबी तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट करता है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 64 मेगापिक्सल का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मुख्य कैमरा दिया गया है, जिसके साथ एक सेकेंडरी सेंसर और एलईडी फ्लैश भी मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

प्रीमियम और ईवी सेगमेंट पर होंडा का फोकस

त्योहारी सीजन में कई नए उत्पाद होंगे लॉन्च

ग्रामीण मांग, प्रीमियम सेगमेंट और महिलाओं की भागीदारी से बढ़ेगी बिक्री

इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो के विस्तार पर भी कंपनी का फोकस

नई दिल्ली बीआर न्यूज नेटवर्क
businessremedies.com

जापान की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता होंडा मोटर ने भारत के दोपहिया बाजार की दीर्घकालिक संभावनाओं पर भरोसा जताया है। कंपनी का कहना है कि व्यक्तिगत परिवहन की बढ़ती जरूरत, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में सुधार, प्रीमियम वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता और कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आने वाले वर्षों में बाजार को नई गति देगी। इसी रणनीति के तहत कंपनी ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप नए मॉडल पेश करने और इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी कर रही है।

बाजार की दीर्घकालिक वृद्धि पर भरोसा

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी त्सुत्सुमु ओतानी ने कहा कि कंपनी को भारतीय दोपहिया बाजार की दीर्घकालिक वृद्धि क्षमता पर पूरा विश्वास है। उनका मानना है कि बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचा, व्यक्तिगत परिवहन की बढ़ती आवश्यकता, महिलाओं की बढ़ती कार्यभागीदारी और प्रीमियम वाहनों की मांग उद्योग की वृद्धि को लगातार मजबूती देंगे।

नए मॉडल और त्योहारी सीजन पर फोकस

कंपनी इस वर्ष की दूसरी छमाही में त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कई नए मॉडल बाजार में उतारेगी। होंडा का लक्ष्य ऐसे उत्पाद पेश करना है जो ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप हों और घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात कारोबार को भी मजबूती दें।

उद्योग की मजबूत स्थिति, लेकिन चुनौतियां बरकरार

वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय दोपहिया उद्योग ने ग्रामीण मांग, प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती बिक्री, निर्यात में मजबूती और सरकार की अनुकूल नीतियों के चलते शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, कंपनी का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि जारी रहेगी, लेकिन इसकी रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है। मानसून, ग्रामीण आय, भू-राजनीतिक घटनाक्रम, कच्चे माल की कीमतें और लॉजिस्टिक लागत जैसे कारक दूसरी छमाही के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

ईवी रणनीति और भारत पर बड़ा दांव

होंडा ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रिक वाहन उसकी दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कंपनी बाजार की मांग और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुरूप अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का लगातार विस्तार करेगी। साथ ही भारत को कंपनी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक बाजारों में शामिल बताते हुए यहां दीर्घकालिक और टिकाऊ निवेश तथा मूल्य सृजन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

वित्तीय सेवाओं, डेटा सेंटर और क्लाउड पर बड़ा दांव लगाएगी एयरटेल, 10 साल में किया 3.3 लाख करोड़ का निवेश

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि कंपनी ने पिछले एक दशक में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में 3.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है और अब वृद्धि के अगले चरण के लिए वित्तीय सेवाओं, डेटा केंद्रों और क्लाउड सेवाओं पर बड़ा दांव लगा रही है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में मित्तल ने कहा कि एयरटेल ने नए विकास क्षेत्रों को तैयार करने के लिए सोच-समझकर कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से कंपनी को मजबूत परिणाम मिले हैं और अब उसे वित्तीय सेवाएं, डेटा केंद्र और एयरटेल क्लाउड क्षेत्र में आगे बढ़ने की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि भारती एयरटेल ने अपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) एयरटेल मनी में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। वहीं, कंपनी की डेटा सेंटर इकाई नेक्स्ट्रा ने एक गीगावाट (जीडब्ल्यू) क्षमता विकसित करने की योजना के तहत हाल में एक अरब डॉलर (करीब 9,500 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। मित्तल ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एयरटेल मनी को गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, 'यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत में वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य की दिशा में भी अहम कदम है।' मित्तल ने कहा कि एयरटेल मनी को आने वाले वर्षों में पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण, क्लाउड सेवाओं के बढ़ते उपयोग और डेटा को देश में ही रखने की जरूरतों के कारण नेक्स्ट्रा अगले कुछ वर्षों में एक गीगावाट क्षमता तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मित्तल ने कहा, 'हमारे तीसरे विकास इंजन एयरटेल क्लाउड को शुरुआती दौर में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हमारी सुरक्षित और दूरसंचार स्तर की क्लाउड सेवा भारतीय बाजार की उभरती जरूरतों को पूरा करती है। इससे ग्राहकों को भारत में ही संचालित और सुरक्षित विश्वस्तरीय क्लाउड सेवाएं लागत प्रभावी तरीके से मिलती हैं।' उन्होंने बताया कि एयरटेल क्लाउड सेवाओं के लिए कंपनी ने 24 से अधिक सौदे किए हैं। मित्तल ने कहा कि सरकार की ओर से क्लाउड, कृत्रिम मेधा (एआई) और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियां निवेश को गति देंगी और इस क्षेत्र के परिवेश को मजबूत करेंगी।

विविध

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 14 जुलाई को सात ईएसआई स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

केंद्रीय श्रम और रोजगार डॉ. मनसुख मांडविया 14 जुलाई 2026 को तेलंगाना के सनथनगर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल से देशभर में सात कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से रविवार को दी गई।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री सनथनगर स्थित ईएसआईसी अस्पताल के नए ओपीडी ब्लॉक का प्रत्यक्ष उद्घाटन करेंगे और छह परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जिसमें असम के बेल्टोला में उन्नत 200 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल, तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदुर में 100 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल, आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में ईएसआईसी अस्पताल, गुजरात के सुरेंद्रनगर में ईएसआई औषधालय और शाखा कार्यालय, कोटा के उद्योग नगर में ईएसआई औषधालय और शाखा कार्यालय

और राजस्थान के भवानी मंडी में ईएसआई औषधालय शामिल हैं। लगभग 668 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये चिकित्सा सुविधाएं देशभर में लगभग 53 लाख लाभार्थियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेंगी।

मंत्रालय ने बयान में ईएसआई अस्पतालों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सनथनगर स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नया ओपीडी ब्लॉक एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य सुविधा है जो हैदराबाद, मेडचल-मल्काजगिरि, संगारेड्डी, रंगा रेड्डी और महबूबनगर जिलों सहित पूरे तेलंगाना में 12,30,183 बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को आधुनिक, व्यापक सेवाएं प्रदान करेगा। वहीं, बेल्टोला स्थित ईएसआईसी अस्पताल असम और मेघालय के 47 जिलों के साथ-साथ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 41 जिलों के लोगों को सेवाएं प्रदान करता है।

इस सुविधा से 3.42 लाख बीमित व्यक्तियों और कुल मिलाकर लगभग 13.27 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलने की आशा है। मंत्रालय के बयान में आगे कहा कि 100 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल श्रीपेरुम्बुदुर में स्थित है, जो भारत के प्रमुख विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है। अस्पताल में ओपीडी, आपातकालीन कक्ष, प्रसव कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, आईपीडी, एक्स-रे और लैब फार्मेसी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों के 5.5 लाख से अधिक बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। सुरेंद्रनगर जिले में ईएसआईसी योजना के अंतर्गत लगभग 9,192 बीमित व्यक्ति शामिल हैं। ईएसआई औषधालय और शाखा कार्यालय से लगभग 35,000 लाभार्थियों को ईएसआईसी की चिकित्सा देखभाल और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। यह एकीकृत सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा परामर्श, आवश्यक दवाएं और अन्य चिकित्सा लाभ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगी। कोटा स्थित ईएसआई डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय, कोटा के औद्योगिक क्षेत्र में रहने और काम करने वाले बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों की एक बड़ी संख्या को सेवाएं प्रदान करेगा। यह सुविधा अपने कार्यक्षेत्र में 1,500 से अधिक नियोक्ता ाओं और लगभग 75,000 बीमित व्यक्तियों और उनके 291,000 आश्रितों को लाभ पहुंचाएगी।

पॉलिसीबाजार ने बीमा जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एंबेसडर बनाया

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

बीमा मंच 'पॉलिसीबाजार' ने दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। इसके साथ ही कंपनी ने स्वास्थ्य और 'टर्म' बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। पॉलिसीबाजार ने एक बयान में कहा कि बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के वर्ष 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य के अनुरूप यह जागरूकता अभियान देश के हर हिस्से में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कंपनी ने कहा कि अमिताभ बच्चन कई पीढ़ियों से भारतीय परिवारों में भरोसे, जिम्मेदारी और आश्वासन के प्रतीक रहे हैं।

उद्योगों का कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद कर सकती हैं सौर तापीय प्रौद्योगिकियां: रिपोर्ट

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

सौर तापीय प्रौद्योगिकियां जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और भारत को निम्न-कार्बन औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद कर सकती हैं। शुक्रवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया। सौर तापीय प्रौद्योगिकी के तहत सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त की जाती है, जिसे संग्रहीत कर बाद में बिजली उत्पादन या औद्योगिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता है। यह सौर पैनल से अलग हैं।

'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट' (टेरी) ने यह अध्ययन रिपोर्ट 'औद्योगिक कार्बन मुक्ति के लिए सौर तापीय ऊर्जा पर नीति' विषय पर जारी की है। टेरी की महानिदेशक डॉ. विभा धवन ने एक बयान में कहा, ''भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ने का लक्ष्य इस बात पर निर्भर करता है कि छोटी एवं मझोली इकाइयों को मजबूत बनाया जाए ताकि वे सस्ती वित्तीय सहायता, सफल प्रायोगिक परियोजनाओं और बाजार आधारित ईएसजी प्रोत्साहनों के जरिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी बाधाओं से उबरने में मदद कर सके।''

इस रिपोर्ट में सौर तापीय प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। इनमें समर्पित संस्थागत सहयोग, दीर्घकालिक वित्तपोषण, वित्तीय प्रोत्साहन और अनुकूल नीतिगत ढांचे के साथ 'राष्ट्रीय सौर तापीय मिशन' शुरू करने की सिफारिश शामिल है।

वर्ष 2032 तक भारत का ईवी कंपोनेंट बाजार बढ़कर 3.55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है: रिपोर्ट

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपोनेंट बाजार वर्ष 2025 के 41,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2032 तक करीब आठ गुना होकर 3.55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस (आईईएसए) और कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस (सीईएस) की रिपोर्ट में कहा गया है कि बैटरी पैक, मोटर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घरेलू ईवी सप्लाई चेन की तेज़ वृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। यह रिपोर्ट नई दिल्ली के यशोभूमि (आईआईसीसी) में आयोजित इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2026 के दौरान जारी की गई। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2025 से 2032 के बीच इस बाजार में 38 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) रहेगी, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में बैटरी पैक का हिस्सा ईवी कंपोनेंट बाजार में आधे से अधिक रहेगा। वहीं, वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा ड्राइवट्रेन इंटीग्रेशन बढ़ाने के साथ मोटर, इन्वर्टर और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) की मांग भी तेजी से बढ़ेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान 3.14 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कारोबारी अवसर पैदा होगा। इसका सबसे अधिक लाभ उन भारतीय

कंपनियों को मिलेगा जो अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), विनिर्माण क्षमता और मजबूत सप्लाई चेन में निवेश करेंगी। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ईवी क्षेत्र का भविष्य अपनी तकनीक, मजबूत स्थानीय सप्लाई चेन और बौद्धिक संपदा (आईपी) विकसित करने पर निर्भर करेगा, जो आने वाले दशक में देश की ई-मोबिलिटी को मजबूती देगा। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रदर्शकों और 10,000 से ज्यादा उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया। यहां नीतिगत चर्चाएं, तकनीकी विचार-विमर्श और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार के भारत-खाड़ी निवेश एवं व्यापार आयुक्त डॉ. इयान मार्टिनस ने कहा, 'पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ केवल महत्वपूर्ण खनिजों के आपूर्तिकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि ईवी ाति में नवाचार और निवेश साझेदार के रूप में भी काम करने के लिए तैयार है।' सीईएस की कंसल्टिंग निदेशक अवंतिका सतीश ने कहा कि भारत के ईवी कंपोनेंट बाजार में तेजी से हो रही वृद्धि यह दिखाती है कि देश तकनीक और विनिर्माण के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बैटरी पैक और इन्वर्टर अभी भी सबसे अधिक आयात पर निर्भर कंपोनेंट हैं। दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रिक वाहन की कुल लागत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। वहीं, मोटर और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) का स्थानीय उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इनका विकास सॉफ्टवेयर आधारित है और इनमें पूंजी निवेश अपेक्षाकृत कम लगता है।

प्रकाशक एवं मुद्रक पुनीत जैन द्वारा सिंघवी पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के लिए आकाशदीप प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स सेक्टर नं.11, अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर-302020 जयपुर से मुद्रित एवं 217, सैकंड फ्लोर, ओके प्लस स्क्वायर, सेक्टर 7, मानसरोवर, जयपुर से प्रकाशित। संपादक : पुनीत जैन मो. 9929106227, आर.एन.आई नं.: RAJHIN/2013/54166, पोस्टल रजि. नं. जयपुर सिटी/006/2024-26, E-Mail: remediesbusiness@gmail.com